

सच्चाई से सबर

वर्ष-10

अंक-232

जयपुर, शनिवार, 21 फरवरी 2026

मूल्य-4 रुपये

पैक्स सिलिका समझौते पर भारत ने किए हस्ताक्षर, एआई-सप्लाई चेन सुरक्षा से जुड़ा है प्रयास

अब चिप और मिनरल सप्लाई चेन होगी सेफ

चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएंगी

नई दिल्ली

भारत ने आज औपचारिक रूप से अमेरिका की अगुवाई वाली पहल 'पैक्स सिलिका' में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज (एआई) और सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। वहीं इस हस्ताक्षर के बाद ट्रंप सरकार में मंत्री जैकब हेल्बर्ग ने कहा, पैक्स सिलिका इस बात की घोषणा है कि भविष्य उन्हीं का है जो निर्माण करते हैं और जब स्वतंत्र लोग एकजुट होते हैं। इस घोषणा में कहा गया है कि एआई भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है और सुरक्षित सप्लाई चेन किसी भी देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।

वैधान बोलें- सेमीकंडक्टर का हब बनेगा भारत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिकी आर्थिक मामलों के सचिव जैकब हेल्बर्ग ने इसपर



साइन किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब पैक्स सिलिका का हिस्सा बन गया है, जिससे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर को बड़ा फायदा होगा।

उन्होंने बताया- भारत में पहले से ही 10 प्लांट्स पर काम चल रहा है। बहुत जल्द देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वैष्णव ने यह भी साझा किया कि भारतीय इंजीनियर अब देश में ही एडवांस '2-नैनोमीटर' चिप डिजाइन कर रहे हैं।

अमेरिका बोला- भारत का प्रवेश सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं

समित में शामिल अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस गठबंधन में भारत की एंटी को रणनीतिक रूप से अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा, 'भारत के पास ऐसा टैलेंट है जो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकता है। भारत की इंजीनियरिंग गहराई इस गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आने वाले समय में करीब 10 लाख अतिरिक्त स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी और दुनिया की यह उम्मीद भारत से ही है। उन्होंने कहा, 'देश के पास अब एक साफ दिशा और लक्ष्य है। हमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडरशिप लेनी है।

इंडिया एआई समिट की बड़ी कामयाबी

250 अरब डॉलर का होगा निवेश, 70 से अधिक देश घोषणापत्र पर करेंगे हस्ताक्षर

नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई समिट' भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हो रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आयोजन को एक बड़ी सफलता करार दिया है। इस वैश्विक महासम्मेलन में न केवल बुनियादी ढांचे के लिए 250 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हासिल हुआ है, बल्कि 70 देशों ने भारत के कूटनीतिक नेतृत्व में 'दिल्ली घोषणापत्र' पर अपनी सहमति भी जता दी है। आसान शब्दों में कहें तो, यह समिट भारत को तकनीकी दुनिया में एक नए ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है।

इस सिखर सम्मेलन का सबसे अहम कूटनीतिक हिस्सा 'दिल्ली घोषणापत्र' रहा है। शुरुआत को 20 फरवरी 2026 को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि अब तक 70 राष्ट्र इस घोषणापत्र पर



हस्ताक्षर कर चुके हैं और कई अन्य देशों के साथ बातचीत अभी भी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शनिवार को इस आयोजन के समापन तक सहमति जताने वाले देशों का अंतिम आंकड़ा 80 को पार कर जाएगा। इस दिल्ली घोषणापत्र की विस्तृत रूपरेखा और इसके अहम बिंदुओं को शनिवार को पूरी पारदर्शिता के साथ दुनिया के सामने साझा किया जाएगा।

भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत को घरेलू स्तर पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आईटी मंत्री ने बताया कि इस प्रदर्शनी में पांच से अधिक आगंतुकों ने हिस्सा लिया, जो देश में उन्नत तकनीक के प्रति भारी उत्साह को दर्शाता है।

संघ का मूल उद्देश्य सत्ता नहीं हिन्दू समाज का संगठन करना है : भागवत

मेरठ। आरएसएस के संरक्षक कल डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी वर्ग विशेष के विरोध या स्वार्थ के लिए नहीं बना है। संघ को किसी प्रकार की सत्ता भी नहीं चाहिए। संघ का मूल उद्देश्य समस्त हिन्दू समाज का संगठन करना है। यदि संघ को समझना है तो संघ के अन्दर आना होगा। संघ के स्वयंसेवक आज विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

एक अप्रैल से सिर्फ फास्टैग और यूपीआई से ही कटेगा टोल टैक्स

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद करने का ऐलान किया है। देश में एक अप्रैल से टोल शुल्क केवल फास्टैग या यूपीआई से लिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक देशभर में 1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी। यह पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत तकनीक-आधारित, तेज और निर्बाध राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि अभी तक अगर कोई वाहन बिना वैध फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उससे दोगुना शुल्क लिया जाता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका

अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से सुनाया फैसला

वॉशिंगटन

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिली बड़ी हार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत एकतरफा रूप से लगाए गए टैरिफ पर केंद्रित है, जिसमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए व्यापक



पारस्परिक टैरिफ भी शामिल हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईपीए) के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से आने वाले सामानों पर व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।

बहुमत से ट्रंप के टैरिफ को दिया झटका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ को खत्म कर दिया है। इस फैसले से वैश्विक व्यापार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, मुद्रास्फीति के रक्षकों और देश भर के घरेलू वित्त पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

कान्हा ग्रुप पर आयकर की छापेमारी जारी, पांच करोड़ की ज्वेलरी बरामद

जयपुर

राजस्थान की प्रसिद्ध फूड चेन कान्हा रेस्टोरेंट समूह पर आयकर विभाग की कार्रवाई शुरुआत तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार सुबह शुरू हुई छापेमारी में जयपुर सहित छह शहरों और मुंबई तक फैले 33 ठिकानों पर संचय किया जा रहा है। जयपुर में सर्वाधिक 26 परिसरों-कार्यालय, गोदाम और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच चल रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान एक ठिकाने पर दीवार के पीछे बना खुफिया कक्ष मिला। संदेह होने पर

दीवार तोड़ी तो भीतर मजबूत स्ट्रॉंग रूम मिला। जहां से करीब पांच करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद हुई। सरकारी मूल्यांकन कर्ता आभूषणों का आकलन कर रहे हैं। अब तक करीब एक करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए जा चुके हैं। उससे यह साफ है यह टैक्स चोरी का आंकड़ा सौ करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। इसके अलावा टीम को दस बैंकों के लॉकरों की ओर जानकारी मिली है। उन्हें खुलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार लॉकरों में बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और सोना मिलने की आशंका है।

सीजेआई बोले-मेरे नाम से नाइजीरिया में बन रहीं फर्जी साइट्स

जयपुर

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- मेरे नाम से हर दूसरे दिन नई साइट बन जाती हैं। उसमें मेरे कई फोटोग्राफ डाल दिए जाते हैं। उन्होंने कहा- मैं आपको अपना एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। हर दूसरे दिन मेरे नाम पर एक नई साइट देखता हूँ। मेरे एक-दो शुभचिंतक हैं, जो मेरे मोबाइल पर मैसेज भेज देते हैं और कहते हैं कि आपके नाम पर नई साइट बनी है। हाल ही कि कुछ तस्वीरों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, वह भी उन साइट्स में अच्छी तरह से लगाई हुई थी। सिर्फ यही नहीं उन साइट से अलग-अलग



तरह के मैसेज भी भेजे जा रहे थे। यह सब मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा- मैंने तुरंत साइबर क्राइम को इसकी सूचना दी। इससे उन लोगों को ढूँढ पाए, लेकिन दुर्भाग्य से वह सारी साइट्स नाइजीरिया से संचालित हो रही थी। यह इस अपराध की जटिलता है। साइबर क्राइम की कोई सीमा नहीं।

सेमिनार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में स्पेशल साइबर कोर्ट बनाने की घोषणा की। धरूने कहा- कोई क्राइम जमीन पर करे या स्क्रीन के पीछे करे, उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। जस्टिस पुषेंद्र भाटी ने कहा- जिस तरह से स्कूल में घंटी बजती है, उसी तरह से हमें पता लगता है कि बम की धमकी आ गई है।

लालसोट में महिला से गैंगरेप और हत्या मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा

दौसा

लालसोट में महिला से दुष्कर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। एडीजे त्रस्तु चौधरी ने शुरुआत को सजा का ऐलान किया। इससे एक दिन पहले गुजरात को कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष लोभक अधियोजक महावीर सिंह किशानावत के अनुसार 23 अप्रैल 2022 को जयपुर की महिला अपने पीछे आ रही थी। वह बस स्टैंड पर उतरकर पैदल घर की ओर जा रही थी। उसी समय एक

14 वर्षीय नाबालिग उसी दिशा में जा रहा था। इसी दौरान संजू मीणा (23) और कालू मीणा (27) कार में वहां पहुंचे और दोनों को लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठा लिया। नाबालिग आरोपी गांव का ही रहने वाला था। रास्ते में नाबालिग का घर आने पर उसे उतार दिया, जबकि महिला को आगे छोड़ने का आश्वासन देकर कार में बिठाए रखा। आरोपी महिला को करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव के सुनसान नदी क्षेत्र में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। वादात के बाद आरोपियों ने महिला के जेवर व नकदी भी लूट ली। महिला द्वारा

घरवालों को घटना बताने की बात कहने पर आरोपियों ने स्कोर्फ से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं होने पर दूसरे गांव में स्थित एक कुएं में शव फेंक दिया। महिला की गुमशुदगी और नाबालिग के बयान के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर महिला का शव कुएं से बरामद किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 45 गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों ने घटना से जुड़े तथ्य प्रस्तुत किए।

स्कूल की दीवार गिरी, छात्रा की मौत

बांस की बल्लियों के सहारे खड़ी थी 8 फीट की दीवार

जालोर

जालोर में प्राइवेट स्कूल की दीवार गिरने से 6 साल की छात्रा की मौत हो गई। स्कूल में सीमेंट के ईंटों की दीवार के ऊपर बांस की बल्लियों लगाकर उस पर तिरपाल डालकर कमरा बनाया गया था। बच्ची स्कूल परिसर में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक दीवार भरभराकर ढह गई और बच्ची ईंटों के नीचे दब गई। हादसा सायला थाना क्षेत्र के बावतरा गांव स्थित मरुभर शिक्षण

श्रीगंगानगर में दो हाईवे साढ़े-चार घंटे रहे बंद



प्रदर्शनकारी किसान बोले- 26 फरवरी को कलेक्ट्रेट के बाहर डालेंगे महापड़ाव

श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर में किसानों ने सड़क के बीच ट्रैक्टर खड़े कर दो हाईवे जाम कर दिए थे। इसके बाद किसान ह्रा-911 के फूसवाला टोल प्लाजा और सीसी हेड पर पदमपुर स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टोटी का पुतला फूँका।

किसानों का कहना है कि पंजाब में फिरोजपुर फीडर पर रिकंस्ट्रक्शन के कारण नहरबंदी के 32 दिन बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा। 2600 वयूसेक की जगह 1500 वयूसेक पानी छोड़ने का वादा किया गया था, लेकिन एक दिन भी पूरी मात्रा नहीं दी गई। 25 फरवरी को नहरबंदी खत्म होने वाली है। यदि बोकारो कैनाल में पूरा पानी नहीं छोड़ा गया तो गंगानहर क्षेत्र की फसलें तबाह हो सकती हैं। इस मांग को लेकर किसानों ने शुरुआत सुबह 11:30 बजे जाम कर दिया था। हालांकि साढ़े चार घंटे बाद शाम चार बजे जाम खत्म किया।

जल बोर्ड के गड्डे में गिरने से युवक की मौत मामले में ठेकेदारों को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में जल बोर्ड के गड्डे में गिरने से युवक की मौत के मामले में सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार 2 ठेकेदार और एक सहायक ठेकेदार को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है और अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एडिशनल सेशन जज हरलीन कोर ठेकेदार हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट वॉरंट जारी किए थे और कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है। कोर्ट ने कहा कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी की देर रात कमल भयानी (25) की दिल्ली में जल बोर्ड की कस्ट्रक्शन साइट पर खोदे गड्डे में गिरने से मौत हो गई थी। 16 फरवरी की सुबह 8 बजे पीसीआर कॉल मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हादसे का पता चला। जांच एजेंसी को उनसे कस्टडी में पूछताछ करनी है। जांच अभी शुरुआती स्टेज में है, और जांच एजेंसी केस से जुड़ी जरूरी चीजें इकट्ठा करने में जुटी है। कहा जाता है कि एलीकेंट जांच एजेंसी की पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था और टालमटोल कर रहा था। अपराध की गंभीरता और उसके सामाजिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस एलीकेशन को मंजूरी देने का कोई आधार नहीं बनता। आवेदक की मौजूदा एंटीसिपेटरी बेल एलीकेशन खारिज की जाती है।

पंजाब में सिविल और मिनी सचिवालय सहित पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में सिविल सचिवालय और मिनी सचिवालय के साथ पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को पूरे परिसर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मुख्य द्वारों को बंद कर लोगों के प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है। सदिध वस्तुओं की तलाशी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। सूत्रों के अनुसार धमकी किसी संदेश या ईमेल के माध्यम से मिली है। हालांकि अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता।

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौत, इलाके में पसरा मातम

मथुरा (एजेंसी)। यूपी के मथुरा जिले के नगला देवीया के पास एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। इस हादसे में कार सवार चार युवकों की मौत हो गई। मृतकों में तीन युवक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा बुधवार शाम को हुआ। मारुति कार में सवार चार दोस्त किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महावन जा रहे थे। नगला देवीया के पास कार की रफ्तार तेज होने के कारण वालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे नहर में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही मगोरों थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला। कार के अंदर फंसे युवकों को जब तक बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए युवकों में से तीन की पहचान हो गई है, जबकि एक की शिनाख्ती की कोशिश की जा रही है। मृतकों में राहुत वर्मा (23) निवासी महावन, पेशे से दर्जी। अभित (23) निवासी प्रेमनगर कलां, छात्र और मोहित (22) निवासी महावन, ला का छात्र था। बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ, वह राहुत वर्मा के भाई सजजन सिंह की थी। एसापी देहात ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है। एक साथ चार युवकों की मौत से महावन और बलदेवगढ़ में सनाटा पसरा है।

10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां... दिल्ली सरकार करेगी जख्त

-दिल्ली परिवहन विभाग ने जारी की सार्वजनिक सूचना



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी में तरा उम्र पार कर चुकी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अब 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, जिन्हें 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' माना गया है, बिना किसी पूर्व नोटिस के जब्त हो सकती हैं। यह कार्रवाई केवल सड़कों पर चल रही गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पार्किंग, खुले मैदान या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खड़े बनें पार पार लागू होगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुकी गाड़ियों को दिल्ली में रखने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसी गाड़ियां राजधानी में दिखाई देती हैं, तब उन्हें कानून के तहत जब्त कर सीधे स्कैप (कबाड़) के लिए भेजा जा सकता है। यह कदम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण मानकों के सख्त पालन के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पुरानी गाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर उन्हें दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर कर लें। इससे वे जब्त की जाने वाली गाड़ियां से बच सकते हैं। विभाग का कहना है कि आने वाले समय में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बीएस-3 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों की जानकारी समय रहते प्राप्त करें और आवश्यक कदम उठाएं, ताकि अचानक होने वाली कार्रवाई से किसी प्रकार की असुविधा न हो।

'वंदे मातरम' विवाद पर शशि थरूर... देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने 'वंदे मातरम' को लेकर चल रही बहस पर साफ कहा कि किसी भी नागरिक को गाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस की आलोचना कर कहा कि देशभक्ति दिल से होती है, और कानून बनाकर इस गाने को जबनन किसी की जुबान पर नहीं लाया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं कि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' अब सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरा गाना अनिवार्य होगा।

कांग्रेस नेता थरूर ने इस दौरान 'वंदे मातरम' के इतिहास का उल्लेख किया। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों को प्रेरित करता था। उन्होंने कहा कि आज एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में राज्य और व्यक्तिगत अंतरात्मा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 'वंदे मातरम' गाती थी, लेकिन देश की धार्मिक विविधता को देखकर 'जन गण मन' को राष्ट्रीय



चुना गया। संविधान सभा ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का समान दर्जा दिया, ताकि स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका सम्मानित हो और किसी समुदाय को अलग-थलग न किया जाए। यह एक सोच-समझकर किया गया समझौता था। कांग्रेस नेता थरूर ने खींदनाथ टैगोर की

भूमिका का भी जिक्र किया। टैगोर ने 1896 में गीत को संगीतबद्ध किया और 1937 में सुझाव दिया कि सार्वजनिक मंचों पर केवल पहले दो अंतरे गाए जाएं। शुरुआती पंक्तियां मातृभूमि को प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीकात्मक वर्णन करती हैं, जिसे सभी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बाद

संजय राउत के बयान पर पवन खेड़ा कि प्रतिक्रिया... उनके बयान पर इंडिया ब्लॉक में विचार होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी संजय राउत के हालिया बयान पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा, वह एक वरिष्ठ नेता हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है, तब निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी इस बयान के बारे में विचार कर तय करने वाले हैं कि क्या किया जाए है। इसके पहले शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इंडिया ब्लॉक के कामकाज की आलोचना कर आरोप लगाया कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर ही सक्रिय होता है और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार समन्वय का अभाव है।

मुंबई में राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का काम लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर शुरू होता है। तब तक किसी के बीच कोई संवाद नहीं होता। तब तक इंडिया ब्लॉक में जनता क्या कर रही है, यह किसी को नहीं पता होता। उन्होंने इस जोर दिया कि संसद के अंदर मुद्दों को

उठाना ही काफी नहीं है, खासकर तब जब विपक्षी नेताओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र कर राउत ने कहा, वे राहुल गांधी को संसद में बोलने तक नहीं देते। क्या हम बाहर कुछ कर सकते हैं?

राउत ने तर्क दिया कि गठबंधन को पूरे राजनीतिक चक्र में सक्रिय रहना चाहिए, न कि केवल आम चुनाव से पहले। उन्होंने किसानों की परेशानी, कानून व्यवस्था और मणिपुर की स्थिति सहित कई गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया, जिन पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। देश में इतनी सारी समस्याएँ हैं।

मुस्लिम आरक्षण रद्द करने पर भड़की कांग्रेस ने कहा- बदले की राजनीति के सिवाए कुछ नहीं

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की महायुक्ति सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के 2014 के पुराने आदेश को औपचारिक रूप से रद्द करने के फैसले ने राज्य की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। जहाँ सत्ता पक्ष इसे केवल एक कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकता बता रहा है, वहीं विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है।

यह विवाद 2014 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय को विशेष पिछड़ वर्ग श्रेणी के तहत 5 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इस नीति को बाँबू हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसने मराठा आरक्षण को तो खारिज कर दिया था, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम आरक्षण को आंशिक रूप से बरकरार रखा था। हालांकि, बाद में आई भाजपा-शिवसेना सरकार ने इस अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दिया, जिससे यह समय सीमा समाप्त होने के बाद निष्प्रभावी हो गया था। अब वर्तमान सरकार ने उसी पुराने आदेश (जीआर) को आधिकारिक रूप से रद्द करने का प्रस्ताव जारी किया है।



कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों से शपथ के समय सभी के इस नीति को बाँबू हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसने मराठा आरक्षण को तो खारिज कर दिया था, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम आरक्षण को आंशिक रूप से बरकरार रखा था। हालांकि, बाद में आई भाजपा-शिवसेना सरकार ने इस अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दिया, जिससे यह समय सीमा समाप्त होने के बाद निष्प्रभावी हो गया था। अब वर्तमान सरकार ने उसी पुराने आदेश (जीआर) को आधिकारिक रूप से रद्द करने का प्रस्ताव जारी किया है।

उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) शिवसेना का रुख चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के महीनों में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नरम रुख दिखाने वाली पार्टी ने इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है। पार्टी सांसद संजय राउत ने केवल इतना कहा कि इस विषय पर बाहर चर्चा करने के बजाय आगामी विधानसभा सत्र में अपनी बात रखी जाएगी। वहीं, शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरक्षण का यह मुद्दा राज्य में धुंवीकरण और तीखी राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है।

अरुणाचल के करीब परमाणु हथियारों का जाल बिछा रहा चीन, भारत के लिए खतरे की घंटी

-चीन का यह परमाणु विस्तार दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की सेना न्यूक्लियर हथियारों के दम पर डराने के पैंतरे आजमा रही है। दुनिया की नजरों से छुपकर चीन के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, जिसका कच्चा चिट्ठा अब सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दिया है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब परमाणु हथियारों का जाल बिछा रहा है। चीन का यह बेलगाम परमाणु विस्तार दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा

खतरा बन गया है। सिचुआन की पहाड़ियों में छिपे ये ठिकाने सीधे तौर पर भारत के पूर्वी इलाकों के लिए एरलट हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि सिचुआन की घाटियों में दो प्रमुख जगहों पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जितोंग घाटी में नए बंकर और मजबूत पायलटान नेटवर्क देखे गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जगह का उपयोग हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है, जो परमाणु वारहेड को ट्रिगर करने के लिए जरूरी है। पिंगटोंग घाटी में प्लूटोनियम पिट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो परमाणु बम का कोर होते हैं, यहाँ की सुरक्षा इतनी सख्त है कि यह किसी किले जैसी दिखती है।

बता दें सिचुआन, अरुणाचल प्रदेश से भौगोलिक रूप से सिर्फ 800 किमी दूर है। चीन ने पहले ही अरुणाचल को अपना 'कोर इंटरस्टेड' घोषित कर दिया है। परमाणु शक्ति का विस्तार चीन को सीमा पर एडवांटेज देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपने परमाणु जखीरे को इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वह अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपने परमाणु हथियारों की पोजीशन दिखाकर डराने की स्थिति में ला सके। 2026 की शुरुआत तक चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु वारहेड हो चुके हैं और 2030 तक यह संख्या 1,000 के पार जाने का अनुमान है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है।

बता दें सिचुआन, अरुणाचल प्रदेश से भौगोलिक रूप से सिर्फ 800 किमी दूर है। चीन ने पहले ही अरुणाचल को अपना 'कोर इंटरस्टेड' घोषित कर दिया है। परमाणु शक्ति का विस्तार चीन को सीमा पर एडवांटेज देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपने परमाणु जखीरे को इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वह अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपने परमाणु हथियारों की पोजीशन दिखाकर डराने की स्थिति में ला सके। 2026 की शुरुआत तक चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु वारहेड हो चुके हैं और 2030 तक यह संख्या 1,000 के पार जाने का अनुमान है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है।



नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी... यात्रियों को लंबी लाइनों और देरी का सामना करना पड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के चलते हड़कंप मच गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरलाइंस द्वारा बुकिंग और चेक-इन के लिए इस्तेमाल होने वाले नेविटोर सिस्टम के सर्वर में समस्या आ गई। इस वजह से यात्रियों को लंबी लाइनों और देरी का सामना करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह खराबी सुबह करीब 6-45 बजे सामने आई और तकनीकी टीम ने करीब 7-30 बजे तक ठीक किया। इस दौरान एयरलाइंस को यात्रियों की जानकारी मैन्युअल रूप से अपडेट करनी पड़ी, जिससे सुबह की भीड़ में असुविधा बढ़ गई और कुछ उड़ानें प्रभावित हुईं। इसतरह मुंबई एयरपोर्ट पर भी ऐसी स्थिति देखी गई। नेविटोर सिस्टम की खराबी के कारण यात्रियों को चेक-इन काउंटर पर लंबा इंतजार करना पड़ा और भीड़भाड़ की शिकायतें सामने आईं। नेविटोर सिस्टम एयरलाइन टिकट बुकिंग, चेक-इन और बोर्डिंग जैसी सुविधाओं के लिए अत्यंत जरूरी है। इसके टप होने पर एयरलाइंस यात्रियों को समय पर सेवा देने में असमर्थ होती है, इससे देरी और अव्यवस्था होती है। बीते साल नवंबर में भी कई एयरपोर्ट पर तकनीकी गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। दिल्ली के आईजीआईए पर एयर ट्रेफिक कंट्रोल प्रणाली में खराबी के कारण उड़ान संचालन बाधित हुआ था। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने मामले पर स्पष्टीकरण दिया था। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि एयरपोर्ट और एयरलाइंस के लिए तकनीकी सिस्टम की स्थिरता बेहद जरूरी है, और ऐसी खामियों से यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ती है। कूल मिलाकर, गुरुवार की यह तकनीकी दिक्कत यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी का कारण बनी, लेकिन तकनीकी टीम की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ गई।

पीएम मोदी ने रामकृष्ण को स्वामी कह संबोधित किया, ममता का आरोप... बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस के जन्मदिन पर उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहकर संबोधित किया, जो बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ है और महान सत के प्रति सांस्कृतिक असंवेदनशीलता को दिखाता है। ममता बनर्जी ने पोस्ट पर अपनी नाराजगी जताकर कहा कि यह अभूतपूर्व और अनुचित संबोधन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को व्यापक रूप से उकुर या श्री रामकृष्ण के रूप में पूजा जाता है। ममता ने कहा कि परमहंस के देहांत के बाद उनके तपस्वी शिष्यों ने रामकृष्ण मठ और मिशन का गठन किया था, जिन्हें भारतीय परंपरा के अनुसार स्वामी कहा गया। लेकिन स्वयं आचार्य या गुरु



को हेमेशा उकुर कहा जाता रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की समझ की कमी बताकर अनुचित बताया। दरअसल, पीएम मोदी ने गुरुवार को

रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हिंदी में पोस्ट किया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने लिखा कि उनके आध्यात्मिक विचार और संदेश हमेशा

मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहने वाले हैं।

रामकृष्ण परमहंस (1836-1886) दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और विभिन्न धर्मों की एकता तथा आध्यात्मिक सद्भाव का संदेश देने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके शिष्यों में स्वामी विवेकानंद प्रमुख थे, जिन्हें स्वामी उपाधि से संबोधित किया गया। वर्तमान में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ उनकी शिक्षाओं पर आधारित सक्रिय संस्थाएँ हैं। बंगाल में वे उकुर के रूप में सम्मानित हैं, इसलिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के संबोधन को सांस्कृतिक दृष्टि से असंवेदनशील करार दिया। इस विवाद में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के सही प्रयोग पर बहस को फिर से उभारा है, खासकर उन संदर्भों में जहाँ सार्वजनिक नेताओं द्वारा सतों और आचार्यों को संबोधित किया जाता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में टेका माथा, वीडियो वायरल

नई दिल्ली (एजेंसी)। एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में भाग लेने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने दिल्ली के प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेका और श्रद्धालुओं के साथ समय बिताया जो भारत-फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों की इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां वे एक वैश्विक नेता के साथ-साथ एक श्रद्धालु के रूप में नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब के प्रबंधन ने भी उनके आगमन पर विशेष ध्यान दिया और इस यात्रा को यादगार बना दिया। उन्होंने वहां सिख समुदाय की परंपराओं को देखा और श्रद्धा भाव के साथ अपनी प्रार्थना की। इससे पहले देर के दौरान उन्होंने दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह का भी दौरा किया था।

असम में तीसरी बार सत्ता में वापसी को जुटा भगवा दल... कांग्रेस की राह नहीं दिख रही आसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के लिए यहां सत्ता बचाने की चुनौती है। भगवा गुट यदि असम में सरकार बनाने में सफल होता है, तब असम में यह भगवा गुट की हेट्टिक होगी। भाजपा ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को असम विधानसभा में 50 प्रतिशत वोट लाने का लक्ष्य दे दिया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का वोट शेयर 33.2 प्रतिशत था। वहीं, सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस को तब जबरदस्त झटका लगा जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी।

भाजपा अध्यक्ष नवीन के द्वारा दिए गए टारगेट को अगर बीजेपी हासिल कर लेती है, तब असम में सभी दलों का सुपड़ा साफ कर देगी। विपक्ष सिर्फ 20-28 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की लोकप्रियता अभी भी कायम है। वहीं सत्ता में वापस आने के लिए व्याकुल दिख रही कांग्रेस की असम विधानसभा की राह आसान नहीं है। वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा के इस्तीफे से जहां पार्टी आंतरिक चुनौती से जूझ रही



है, वहीं महाजोत में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने को लेकर महाजोत के कई घटकदल दबाव बनाए हुए हैं। असम में अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं।

तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस असम में पार्टी को एकजुट रखने में फ़ायल रही। तमाम कोशिशों के बाद भी बोरा ने आखिरकार पार्टी छोड़ दी। पार्टी को डर है कि भूपेन बोरा के साथ उनके भरोसेमंद कई विधायक और नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इससे मतदाताओं में पार्टी की छवि कमजोर होगी। इसके साथ महाजोत में सीट बंटवारा भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि, 2021 के महाजोत में कई बदलाव हुए हैं। एआईयूडीएफ और बोडोलैंडपीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) दोनों

महाजोत से अलग हो चुके हैं। बीपीएफ अब एनडीए का हिस्सा है, वहीं मौलाना बद्रुल्ला अजमल की अगुआई में एआईयूडीएफ अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं असम जातीय परिपद और अखिल गोर्खा का रायजोर दल अब महाजोत में शामिल है। कांग्रेस ने एजेपी और रायजोर दल दोनों को महाजोत में 11-11 सीट देने की पेशकश की है, पर दोनों दल इससे ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस इन्हें अधिक सीट देती है, तब चुनाव में कांग्रेस को कम सीट पर लड़ना होगा। असम में दूसरे दलों के साथ गठबंधन किए बिना भाजपा की अग्रगण्यता के लिए परसून देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है।



कृषि उपज मंडी में अत्यवस्थाओं से किसान नाराज

आरक्षित प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का कब्जा

स्मार्ट हलचल

बिजौलियाँ। कृषि उपज मंडी बिजौलिया में इन दिनों खरीफ की मुख्य फसल मक्का की खरीद जोरों पर है, लेकिन मंडी परिसर में फैली अत्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान और नाराज नजर आ रहे हैं। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य साधनों से अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, परंतु उन्हें फसल रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चांदजी की खेड़ी के किसान नरेश धाकड़ ने बताया कि किसानों के लिए आरक्षित टीन शेड और प्लेटफॉर्म पर



व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। व्यापारियों द्वारा खरीदी गई फसल को किसानों के लिए बनाए गए विशाल चबूतरे पर रखा जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज खुले में डालनी पड़ रही है। मौसम में बदलाव

और बादलों की आवाजाही के कारण किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है। किसानों का आरोप है कि मक्का की खरीद 1400 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से की जा

मंडी प्रशासन का पक्ष

मंडी कर्मचारी रमेश सेन ने बताया कि मंडी में करीब 70 व्यापारी पंजीकृत हैं और पिछले 20 दिनों से मक्का की खरीद जारी है। प्रतिदिन लगभग एक हजार बोरी उपज मंडी में आ रही है। आगे से खरीद कम होने के कारण भुगतान में कुछ देरी हो रही है। उन्होंने माना कि किसानों के लिए आरक्षित प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों ने खरीदी गई फसल अस्थायी रूप से रखी है और प्लेटफॉर्म छोटा होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि खुले में रखी किसानों की फसल सुरक्षित है। फिलहाल किसानों ने मंडी प्रशासन से व्यवस्था सुधारने, आरक्षित प्लेटफॉर्म खाली करवाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।

रही है, लेकिन भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि नियमानुसार फसल विक्रय के अधिकतम तीन दिनों के भीतर बैंक चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए, जबकि यहां 15 दिन से अधिक समय बाद भुगतान देने की बात कही जा रही है। किसानों

ने इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए मंडी प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। किसानों का यह भी कहना है कि व्यापारी मनमर्जी से भाव तय कर रहे हैं और भुगतान में देरी कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम, सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो होगा जन आंदोलन

स्मार्ट हलचल

शाहपुर। शहर के मुख्य बाजार की जर्जर सड़क को लेकर अब राजनीतिक गर्माहट बढ़ने लगी है। नगर कांग्रेस कमेटी शाहपुर ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि सदर बाजार की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू नहीं किया गया तो नगर में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। नगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश सेन के नेतृत्व में एक सप्ताह पूर्व एडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में मुख्य मांग सदर बाजार की जर्जर सड़क का तत्काल निर्माण करवाने की थी। इस दौरान तहसीलदार ने पीएचडी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर



एक सप्ताह में कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया था। हालांकि एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इसे लेकर नगर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है। रमेश सेन ने कहा कि यदि आगामी 24 घंटे के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो नगर कांग्रेस व्यापारियों के सहयोग से शाहपुरा बंद करवाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि

उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष नमन ओझा, नगर उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा, नगर महामंत्री ओम सिंघी, पूर्व छत्रसंघ अध्यक्ष ओमप्रकाश जाट, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष जयंत जीनार एवं युवा नेता शाहरुख खान भीमपुरा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

निशुल्क नेत्र जांच मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में 91 को दिया परामर्श

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अन्धता निवारण सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान में चार दिवसीय निशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श मोतियाबिंद शिविर आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आज शुभारंभ हुआ जिसमें 25 गांवों के 91 नेत्र रोगियों को परामर्श दिया गया।



समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि डॉ. कृष्णा हेडा फेको सर्जन द्वारा नेत्र रोगियों की निशुल्क जांच कर उन सभी जरूरतमंद रोगियों के सर्जरी हेतु 21 फरवरी को ऑपरेशन किए

भगवान विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की रखी मांग

स्मार्ट हलचल

लाडपुरा। राजस्थान विधानसभा में नियम 295 के अंतर्गत महा विधायक राजेंद्र मीणा ने जागिड़ ब्राह्मण समाज एवं समस्त शिल्पकार वर्ग के आग्रह देव भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती (माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी) पर राजकीय अवकाश घोषित किए जाने संबंधी विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधायक राजेंद्र मीणा ने अपने वक्तव्य में कहा कि भगवान विश्वकर्मा जी सृष्टि के दिव्य शिल्पकार माने जाते हैं। प्रदेश एवं देशभर के कारीगर, शिल्पकार, इंजीनियर तथा औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े सभी वर्ग ब्रह्मा, हवन एवं उत्सव के साथ उनकी जयंती मनाते

हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाजों एवं महापुरुषों की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित कर जनभावनाओं का सम्मान किया गया है। उसी क्रम में जागिड़ ब्राह्मण समाज की यह न्यायोचित एवं सम्मानजनक मांग है कि भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर भी राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। विधायक मीणा ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि प्रदेश की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मांग को स्वीकार कर समाज को सम्मान प्रदान करें। राजेंद्र मीणा ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय लेकर समाज की भावनाओं का सम्मान करेगी।

युवा शक्ति के साथ वैश्य समाज को नई दिशा - आईवीएफ युवा भीलवाड़ा की जिला कार्यकारिणी घोषित

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन युवा इकाई, भीलवाड़ा द्वारा संगठन विस्तार के तहत नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। मनीष बन्ध ने बताया कि संभागीय अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल (सांसद) के निर्देशन एवं प्रदेश मंत्री कल्पेश चौधरी, जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल कांबा, संभागीय युवा अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार झण्णी की सहमति से युवा जिला अध्यक्ष अंकित सोमानी ने कार्यकारिणी का गठन किया। घोषित पदाधिकारियों में जिला महामंत्री हर्षल नागौरी व रमेश जैन, मुख्य सलाहकार योगेश अग्रवाल व महादेव बाहेती, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्ष राठी, जितेंद्र बाठिया, विजय विजयवर्गीय, आशीष शाह (जैन), मनीष सेठी व ऋषभ पोखवाल, कोषाध्यक्ष त्रिदेव मुंदड़,

जिला मंत्री सचिन कांबरा, अंशुल शाह (अग्रवाल), मितेश सोडानी, रवि जैन व योगेश हेड्ड, उपाध्यक्ष रहित अग्रवाल, विशाल सेठी, अभिषेक जागेटीया, राजेश सोमानी व फंज राठी, संगठन मंत्री विकास चौधरी, शंकर ईनानी व मनीष विजयवर्गीय, मोडिया प्रभारी हरिश्चंद्र हिंदुस्थानी (जैन) तथा सोशल मीडिया हेडलर सुधीर अजमेर शामिल हैं। इस दौरान रामेश्वर कांबरा व कल्पेश चौधरी ने संगठन को तहसील एवं ग्राम स्तर तक सक्रिय करने का आह्वान किया। महिला संभाग अध्यक्ष मधु जाजू ने 'घर-घर सदस्य, हर दिल में अभिमान - वैश्य एकता हमारी पहचान' का नारा देते हुए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। संगठन ने 'संघटित वैश्य समाज सशक्त समाज का निर्माण के संकल्प को दोहराया।

अलीगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता की विशेष मुहिम-सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई

- विशेष स्वच्छता टीम द्वारा गली-मोहल्लों, सार्वजनिक चौराहों व सड़कों से सिंगल यूज प्लास्टिक थैलियां व डिस्पोजल कप कट्टों में भरकर किए संग्रहित-लोगों को किया जागरूक

स्मार्ट हलचल

टोंक/अलीगढ़। जिले की अनियारा पंचायत समिति मुख्यालय अलीगढ़ क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच प्रशासक सबिया बी तथा ग्राम विकास अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार नायक सहित वार्ड पंचों की पहल पर शुक्रवार को बीते दो दिनों से लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत कस्बे में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया।



ग्राम पंचायत प्रशासन अलीगढ़ की ओर से गठित स्वच्छता टीम ने, शुक्रवार को कस्बे के प्रत्येक वार्ड, सार्वजनिक चौराहों, गली-मोहल्लों और बाजार क्षेत्र में पहुंचकर सिंगल यूज प्लास्टिक थैलियों, पत्तियों तथा

चाय की होटलों एवं दुकानों के बाहर सड़क पर फेंके गए डिस्पोजल कप व गिलासों को इकट्ठा किया। टीम ने जगह-जगह बिखरे प्लास्टिक कचरे को कट्टों में भरकर संग्रहित किया। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत प्रशासन ने दुकानदारों और मोहल्ला

वासियों से संवाद कर समझाइश दी कि आम रास्तों, गलियों और सड़कों पर कचरा न फैलाए। घरों और दुकानों का कचरा कूड़ेदान में ही डालें तथा कचरा संग्रहण वाहिनियों के आने पर ही कचरा सौंपें। स्वच्छता टीम द्वारा प्लास्टिक कचरा हटाने के बाद गली-

हैं, इसलिए प्लास्टिक उपयोग से बचना आवश्यक है। ग्राम पंचायत प्रशासन अलीगढ़ द्वारा कस्बा क्षेत्र के दुकानदारों एवं ग्रामवासियों को चेतावनी भी दी गई कि शीघ्र ही स्वच्छता समिति द्वारा बाजार का निरीक्षण किया जाएगा। जिन दुकानों पर कचरा पात्र नहीं मिलेगा, उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर कचरा पात्र रखने और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पंचायत समिति अनियारा मुख्यालय अलीगढ़ के खंड विकास अधिकारी शंकर लाल मेघवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत समिति परिसर सहित आसपास की साफ-सफाई करवाई गई तथा

अधीनस्थ कार्मिकों ने भी सहयोग किया। उन्होंने पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया कि वे अलीगढ़ ग्राम पंचायत की चेतावनी भी दी गई कि शीघ्र ही स्वच्छता समिति द्वारा बाजार का निरीक्षण किया जाएगा। जिन दुकानों पर कचरा पात्र नहीं मिलेगा, उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर कचरा पात्र रखने और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पंचायत समिति अनियारा मुख्यालय अलीगढ़ के खंड विकास अधिकारी शंकर लाल मेघवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत समिति परिसर सहित आसपास की साफ-सफाई करवाई गई तथा

प्रशासन की लापरवाही से बाजार में कीचड़, आमजन परेशान



स्मार्ट हलचल | शाहपुरा

नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में प्रशासन की लापरवाही और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में बदलाव के दुष्परिणाम अब आमजन और दुकानदारों को भुगतने पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को रोजाना कीचड़ से होकर गुजरना मजबूरी बन गया है।

हो रही इन घटनाओं से बाजार में आक्रोश का माहौल है।

पूर्व कांग्रेस सेवादल नगर मुख्य संगठक पप्पू पटन ने नगरपालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में बदलाव और लापरवाही के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र प्रभाव से उचित कार्यवाही कर बाजार क्षेत्र की सफाई व मरम्मत करवाई जाए, ताकि आमजन और दुकानदारों को राहत मिल सके। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

पावन-चित्तौड़गढ़ स्वच्छता अभियान का मध्य शुभारंभ

10 हजार कपड़े के बैग वितरित, स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान

स्मार्ट हलचल | चित्तौड़गढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार शुक्रवार को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में 'पावन-चित्तौड़गढ़ स्वच्छता अभियान' का मध्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सांसद सी.पी. जोशी, जिला कलक्टर आलोक रंजन, एनपीसीएल के यूनिट हेड सहित जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की।



पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त चित्तौड़गढ़ के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के तहत राजस्थान परमाणु बिजलीघर (एनपीसीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 हजार कपड़े के बैग नागरिकों को वितरित किए गए। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए जिले को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वास्थ्यप्रद बनाना है। इसके सफल संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर परिषद गार्डन में भव्य लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद सी.पी. जोशी रहे तथा अध्यक्षता जिला कलक्टर आलोक रंजन ने की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विनय पाठक सहित

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी राकेश कुमार पुरोहित ने अभियान की रूपरेखा, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। सामाजिक सरोकार से जुड़े गौरव त्यागी, अनिल इनानी एवं सुधीर जैन सहित अनेक नागरिकों ने भी सक्रिय सहभागिता

निभाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से विशेष शुभारंभ अभियान का विशेष प्रारंभ ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग से किया जाएगा। दुर्ग क्षेत्र को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया गया है। साथ ही शहर के प्रत्येक घर तक कपड़े अथवा पुनः उपयोग योग्य थैलियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि नागरिक बाजार जाते समय स्वयं की थैली साथ लेकर जाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः बंद कर सकें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए तथा अभियान को वाई एवं ग्राम स्तर तक प्रभावी रूप से संचालित करने पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा स्वच्छता पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी गई,

चंबल परियोजना के कार्मिकों की लापरवाही से हजारों लीटर पानी वेस्ट



स्मार्ट हलचल

बेरा। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबल परियोजना की लाइन जगह जगह से लीकेज हैं जिससे हजारों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है जसवंतपुरा चौराहे के पास पाइप लीकेज होने के कारण 2 दिन से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा

है लेकिन कर्मचारियों की अभी तक नौद नहीं खुली जिससे पानी की बर्बादी साफ तौर पर दिख रही है गांव में समय पर पानी उपलब्ध नहीं होता है लेकिन यहां के हालातो पर गौर करने तो जल ही जीवन है कहावत पर बड़ा लगाया जा रहा है। विभागीय उदासीनता जल बरबादी का कारण बन रही है।

रेलवे स्टेशन पर नो-पार्किंग में खड़े 65 वाहनों पर कार्रवाई

यात्रियों की सुरक्षा व आपातकालीन आवागमन सुनिश्चित करने हेतु आरपीएफ का विशेष अभियान

स्मार्ट हलचल | कोटा

यात्रियों की सुरक्षा, स्टेशन परिसर में सुचारु यातायात व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन परिसर में नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।



इस अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े पाए जाने वाले 65 वाहन चालकों के विरुद्ध रेल अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध चालान एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। रेलवे सुरक्षा बल ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने से न केवल यातायात व्यवस्था बाधित होती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं की सुगमता भी प्रभावित होती है।

स्टेशन परिसर में अनुशासन एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों से अपेक्षा की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए रेलवे प्रशासन का सहयोग करें।

रेलवे सुरक्षा बल ने आमजन एवं यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे स्टेशन आने पर अपने वाहनों

उदयपुर में नागरिक सुरक्षा मास्टर ट्रेनिंग पर उठे सवाल, 360 चयन सूची में अनियमितता के आरोप

स्मार्ट हलचल | उदयपुर

जिले में चल रही नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) मास्टर ट्रेनिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 360 मास्टर ट्रेनरों की चयन सूची में अनियमितता के आरोप लगाते हुए स्वयंसेवकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक 31 दिवसीय सेवा एवं बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण का समापन 17 फरवरी को किया गया। इसके बाद 19 फरवरी 2026 से 7 दिवसीय नागरिक सुरक्षा मास्टर ट्रेनिंग



कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें पुराने स्वयंसेवकों और वार्डनों को शामिल किया जाना था।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 360 मास्टर ट्रेनरों की सूची पहले से ही तैयार कर ली गई थी।

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कुछ कर्मचारियों ने अपने चहेते लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से सूची तैयार की। इससे योग्य और मेहनती स्वयंसेवकों को मौका नहीं मिल पाया।

ज्ञापन में कहा गया है कि कई ऐसे प्रशिक्षणार्थी, जिन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन किया और एचसीसी स्काउट सहित अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त किए, उन्हें चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया। वहीं, कथित रूप से कम योग्य लोगों को सूची में शामिल कर लिया गया।

स्वयंसेवकों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेनी चाही तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

कुछ को ड्यूटी से हटाने और नोटिस देने की चेतावनी भी दी गई, जिससे स्वयंसेवकों में नाराजगी फैल गई। शिकायत में मांग की गई है कि 360 मास्टर ट्रेनरों की सूची पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही पात्र और योग्य अभ्यर्थियों को मौका देते हुए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित किया जाए।

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि जांच के आदेश जारी होते हैं तो नागरिक सुरक्षा मास्टर ट्रेनिंग की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सुरौट पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 10 साल से फरार 25 हजार के इनामी डकैत को दबोचा

स्मार्ट हलचल | सुरौट



पुलिस महानिदेशक की ओर से संगठित अपराधियों, माफियाओं और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे 'ऑपरेशन शिकंजा' अभियान के तहत सुरौट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में सुरौट पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी दीवान गुर्जर को धौलपुर के बीहड़ जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है।

करोली एसपी लोकेश सोनवाल ने शुक्रवार की सांय सुरौट थाने में की गई फरार वार्ता में बताया कि आरोपी दीवान पुत्र मुंशी गुर्जर, निवासी बरेड थाना सदर बाड़ी जिला धौलपुर कुख्यात डकैत जगदीश गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है। यह

पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिण्डैन सिटी के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी संसाधनों और सटीक मुखबिरी के आधार पर धौलपुर के बीहड़ जंगलों में लगातार पीछा कर इसे दबोच लिया। यह कार्रवाई साल 2016 में सुरौट कस्बे में हुई एक सनसनीखेज वारदात से जुड़ी हुई है। 28 अगस्त 2016 की रात करीब 1:00 बजे सुरौट निवासी कृष्णा सोनी के घर में हथियारबंद नकाबपोश बदमाश चुस आए थे। बदमाशों ने परिवार को जान से मारने की धमकी देकर तिजोरी की चाबी

मांगी और विरोध करने पर उनके साथ साहपीट की। अपराधी वहां से 4 तोला सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना सुरौट में आईपीसी की धारा 458, 380 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सुरौट पुलिस सात जनों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि दीवान गुर्जर 10 साल से फरार चल रहा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इस महत्वपूर्ण सफलता में थानाधिकारी सोहन सिंह गुर्जर के नेतृत्व वाली टीम का विशेष योगदान रहा। टीम में सहायक उप-निरीक्षक विष्णु कुमार, कार्टेबल योगेंद्र सिंह और देशराज शामिल थे। अब दीवान को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सोनवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दीवान, कुख्यात डकैत जगदीश गुर्जर की गैंग का सक्रिय सदस्य है। इस गैंग का क्षेत्र में काफी खौफ रहा है। गिरोह के मुखिया जगदीश गुर्जर के खिलाफ राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में डकैती, नकदी लूट, नकबजनी सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

अपात्र लाभार्थियों को 28 फरवरी, 2026 तक अन्तिम मौका

उसके बाद गिवअप नहीं करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया 'गिव अप अभियान' रोज नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भीलवाड़ा जिले ने इस अभियान में अब्बल रहते हुए आज तक 250790 लोगों से 'गिव अप' करवाकर ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। इकेवाईसी के माध्यम से 75453 लोग भी एनएफएसए योजना से हटे हैं। इस प्रकार कुल 326243 अपात्र लोगों को एनएफएसए योजना से हटाया गया।

इन अपात्र लोगों के हटने से 271546 पात्र किन्तु वंचित लोगों को एनएफएसए योजना में जोड़ने में जिले को सफलता मिली है। एक ओर जहां एनएफएसए योजना से हटते लोगों पर वहन होने वाली खाद्य, गैस, बीमा, चिकित्सा सब्सिडी से बचत होगी वहीं दूसरी ओर नये एनएफएसए लाभार्थियों को इन चार योजनाओं का लाभ मिल

सकेगा। 'गिव अप' योजना के तहत चार पहिया वाहन मालिकों, सरकारी कार्मिकों, आयकर दाताओं तथा 01 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों ने एनएफएसए लाभ का त्याग कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। 'गिवअप' अभियान ने समाज में जागृति पैदा की है एवं लोग भारी संख्या में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन 'गिव अप' कर सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन कर मिसाल कायम कर रहे हैं। इस अभियान में समाज के हर वर्ग के लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं सोशल, प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

वर्तमान में यह योजना 28 फरवरी 2026 तक के लिए है। 28 फरवरी 2026 तक स्वेच्छ से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 01 मार्च 2026 से 30 रुपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूँ की दर से खाद्यान वसूली की जायेगी।

ग्राम पंचायत कुल्ली में विकास कार्यों की शिकायत पर पहुंची जांच टीम

तहसील दिवस पर की गई शिकायत के 21 बिंदुओं की हुई जांच, अभिलेखों की पड़ताल



स्मार्ट हलचल | खरखेरू/फतेहपुर

विजयीपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कुल्ली में कराए गए विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर जनपद स्तरीय तीन सदस्यीय जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।

ग्राम निवासी शिकायतकर्ता नरसिंह पुत्र धनराज नारायण सहित अन्य ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान बबली देवी पर आरोप लगाया था कि ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में तहसील दिवस पर लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें 21 बिंदुओं पर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था।

शिकायत के आधार पर जनपद से गठित तीन सदस्यीय टीम ग्राम पंचायत कुल्ली पहुंची और संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू की। जांच

के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम सभा की कार्ययोजना से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिनकी टीम ने सचिव कुल्ली की उपस्थिति में जांच की।

जांच अधिकारी शरद विक्रम (सहकारिता विभाग) ने बताया कि शिकायत में विकास कार्यों के फर्जी भुगतान का आरोप लगाया गया था। प्राथमिक जांच में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पड़ताल की गई है। उन्होंने बताया कि कार्य योजना को लेकर शिकायत की गई थी, उनमें से कार्य नहीं किया गया न ही भुगतान किया गया अभिलेखों की भी जांच की जा रही है। गीबोर (नलकूप पुनर्भरण) के संबंध में उन्होंने कहा कि पुराना गीबोर मौके पर नहीं मिला है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद की जाएगी। जांच से संबंधित तथ्यों की सत्यापित प्रति शीघ्र ही शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्मार्ट हलचल | उदयपुर

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर एवं स्ट्रलाइट एड्डिडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज शुक्रवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट उदयपुर में सेवा-पूर्व शिक्षकों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल (टीएलएम) निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन में किया गया।

पीएसटीई प्रभागाध्यक्ष डॉ अंजली कोठारी के अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट उदयपुर में आयोजित इस पहल का उद्देश्य सेवा-पूर्व शिक्षकों में नवाचार, रचनात्मकता तथा स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है। इस प्रतियोगिता में डाइट उदयपुर के डी.एल.एड. प्रथम वर्ष



के कुल 32 सेवा-पूर्व शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विभिन्न विषयों पर नवाचारी एवं उपयोगी टीएलएम प्रस्तुत किए।

प्रतियोगिता का आकलन डॉ अंजली कोठारी एवं श्रीमती सोनिका द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों के टीएलएम का मूल्यांकन उनकी शैक्षणिक उपयोगिता, नवाचार, रचनात्मकता एवं स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के आधार पर किया। इस प्रतियोगिता में डाइट उदयपुर

शांति अपराधी पिछले एक दशक में

के सेवा-पूर्व शिक्षक संजय पटेल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान दीपिका कुंवर, तृतीय स्थान सोनल मीणा ने प्राप्त किया।

प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय टीएलएम निर्माण प्रतियोगिता के द्वितीय चरण में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने संस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे।

यह प्रतियोगिता सेवा-पूर्व शिक्षकों में नवाचारी शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करने तथा राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अभियान प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डाइट प्रिंसिपल शोला काहल्या ने की जबकि एड्डिडिया फाउंडेशन ने आकांक्षा पांडे मुख्य अतिथि एवं डाइट अधिकारी सत्याग्रिय विशिष्ट अतिथि थे। संचालन सुनील विश्णोई ने किया।

'होमस्टे इकाइयों के संचालन में बड़ा बदलाव'

'अब 8 कमरे व 24 बिस्तरों तक की अनुमति'

स्मार्ट हलचल | उदयपुर

प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पर्यटन विभाग ने अधिसूचित राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना, 2026 के अंतर्गत होमस्टे इकाइयों के संचालन से संबंधित प्रावधानों में महत्वपूर्ण

संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों से राज्य में आवास सुविधाओं का विस्तार होने के साथ पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय उदयपुर की संयुक्त निदेशक ने बताया कि पूर्व में लागू प्रावधानों के तहत शुद्ध आवासीय इकाई में संचालित होमस्टे या पेइंग गेस्ट हाउस में अधिकतम 5 कमरों की अनुमति थी। संशोधित व्यवस्था के तहत अब यह सीमा बढ़ाकर अधिकतम 8 कमरे कर दी गई है। इसी प्रकार पूर्व में निर्धारित बिस्तरों

की संख्या में भी वृद्धि करते हुए अब प्रति इकाई अधिकतम 24 बिस्तरों तक की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे आवास क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार संभव होगा।

पूर्व व्यवस्था के अनुसार यह अनिवार्य था कि होमस्टे या पेइंग गेस्ट हाउस इकाई का संचालन संपत्ति स्वामी या उसके परिवार के सदस्य द्वारा उसी आवास में निवास करते हुए किया जाए। संशोधित प्रावधानों में इस शर्त को लचीला बनाया गया है। अब यदि संपत्ति स्वामी स्वयं उस आवास में निवास नहीं करता है, तो वह संचालन के

लिए एक केयरटेकर नियुक्त कर सकेगा। नियुक्त केयरटेकर योजना में निर्धारित नियमों व मानकों के अनुरूप इकाई के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

पर्यटन विभाग के अनुसार इन संशोधनों से योजना अधिक व्यवहारिक, लचीली और संचालन की दृष्टि से सरल बनेगी। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधाओं का विस्तार होगा तथा पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा। अधिक जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय मीणा महासभा में नई नियुक्ति, एडवोकेट राजेश मीणा बने अध्यक्ष

विधि प्रकोष्ठ; संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी

स्मार्ट हलचल | जयपुर

मीणा समाज के सामाजिक एवं संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रीय मीणा महासभा द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठते हुए नई नियुक्ति की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि प्रकाश पक्वड़ी द्वारा जारी आदेश के अनुसार एडवोकेट राजेश मीणा को राष्ट्रीय मीणा महासभा का अध्यक्ष - विधि प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद समाज और संगठन से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

जारी नियुक्ति पत्र में उल्लेख



किया गया है कि संगठन के संविधान में प्रस्तुत अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। नव-नियुक्त पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे महासभा के नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करते हुए संगठन की गतिविधियों को गति दें, समाज के हितों की रक्षा करें तथा मीणा समाज को विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका

निभाएं। विधिक मामलों में संगठन को मिलेगा मजबूत नेतृत्व

संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार एडवोकेट राजेश मीणा के विधिक अनुभव से महासभा को विशेष लाभ मिलेगा। समाज से जुड़े कानूनी मुद्दों, सामाजिक अधिकारों और न्यायिक मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ संगठन के कार्यों को कानूनी रूप से सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका अहम रहेगी।

समाजहित और संगठन विस्तार पर रहेगा फोकस

महासभा की ओर से कहा गया है कि नई नियुक्तियों के माध्यम से संगठन का विस्तार और सक्रियता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट राजेश मीणा को समाज के युवाओं को जोड़ने, कानूनी जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पदाधिकारियों और समाजजन ने दी शुभकामनाएं

नियुक्ति के बाद संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं समाजजनों ने एडवोकेट राजेश मीणा को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में विधि प्रकोष्ठ नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। समाज के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने और संगठन को नई दिशा देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी।

जिला माहेश्वरी महिला संगठन में सर्वसम्मति से हुआ नेतृत्व चयन

भारती बाहेती अध्यक्ष, निशा काकाणी सचिव सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के निर्देशानुसार दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक महिला मंडल के सानिध्य तथा शास्त्री नगर माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में आजाद नगर माहेश्वरी भवन में भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी महिला संगठन की चुनाव प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्विरोध सम्पन्न हुई। जिलाध्यक्ष प्रीति लोहिया ने बताया कि यह प्रक्रिया चुनाव पर्यवेक्षक आशा मंडोवरा तथा चुनाव अधिकारी चंद्रा नामधर के



मार्गदर्शन में संपन्न कराई गई। चयन प्रक्रिया की शुरुआत अतिथियों के द्वीप प्रज्वलन और प्रतीक्षा मेलाना की महेश

वंदना से हुई। मंच संचालन मोना डाड द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रीति लोहिया ने अपने उद्बोधन में

अतिथियों का स्वागत सुंदर पंक्तियों से किया। उपस्थित सभी अतिथियों का उपरना पहनकर आत्मीय स्वागत

किया। आयोजक संस्था शास्त्री नगर माहेश्वरी महिला संगठन अध्यक्ष मधु समदानी ने भी स्वागत भाषण दिया।

इस अवसर पर अध्यक्ष पद के लिए भारती बाहेती, सचिव पद के लिए निशा काकाणी और सचिव सचिव के चयनित किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वे अगले तीन वर्षों तक समाज को और अधिक संगठित और सक्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीमा कोमट, मनोमरा कालिया, संस्था आगीवात, अंकिता राठी, वंदना बाल्दी, सहित जिला महिला मंडल

सदस्यएँ उपस्थित रहीं। सचिव रेखा धूत ने सभी का आभार व्यक्त किया। चुनाव प्रक्रिया सौहार्द, एकता और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिससे संगठन के आगामी कार्यकाल के वेद मंत्रों से तुलसी और सकारात्मक संदेश देखने को मिला। इस अवसर पर सुनीता मनिवार, सुमन सोनी, सोनल माहेश्वरी, वीणा मोदी, आशा पटवारी, काता सोमानी, स्नेह अजमेरा, राधा न्याति, विजय लक्ष्मी समदानी, विनीता तापाणी, राज राठी, प्रफुला राठी, सुनीता बलद्वरा, राखी राठी एवं सभी तहसीलों की बहनें उपस्थित रहीं।

स्मार्ट हलचल

आकोला। श्री मुनिकुल ब्रह्मचर्याश्रम वेद संस्थान बरूंदनी में सप्तम (अंतिम)वर्ष के सभी छात्रों का (दीक्षांत)समावर्तन संस्कार वैदिक विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र जोशी ने समावर्तन संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालकर बताया कि समावर्तन संस्कार हिन्दू धर्म के 16 संस्कारों में से 12वां (कुछ मान्यताओं में 14वां) महत्वपूर्ण संस्कार है। इसका

शाब्दिक अर्थ है 'घर वापस लौटना'। प्राचीन काल में, गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद ब्रह्मचारी का गृह के आश्रम से अपने घर लौटते समय यह विदाई समारोह किया जाता था, जो आज के दीक्षांत समारोह जैसा है। मुरलीधर पंचोली ने कार्यक्रम की अनुशंसा की इस कार्यक्रम में कर्मकांड विद्वान रतनलाल चास्टा ने कार्य के विधिपूर्वक संपन्न करवाया साथ ही हरि शंकर उदय लाल उमाकांत हरीश कुमार की सभी अन्य वैदिक विद्वान उपस्थित हुए।

सिंगोली चारभुजा में तुलसी विवाह सम्पन्न



स्मार्ट हलचल

आकोला। सिंगोली श्याम धार्मिक तीर्थ स्थल पर सालिग्राम जी भगवान की (बारत) शोभा यात्रा निकाली। मंदिर प्रबंधक अर्जुन सिंह सोलंकी ने बताया कि पुजारी परिवार गोविंद पाराशर, अनिल पाराशर, अखिलेश पाराशर ने शालिग्राम भगवान को दूल्हे के रूप में सजा बेवाण में विवाहित कर लक्ष्मीनाथ भगवान व सिंगोली श्याम के बेवाण बारत में शालिग्राम होकर गाजे-बाजे के साथ कस्बे में शोभायात्रा निकालते हुए रतनलाल ,चांदमल ,जगदश चंद्र ,राजेंद्र कुमार ,मनोज कुमार स्वर्णकार के आवास पर तुलसी विवाह करने पहुंचे।

शोभा यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा श्रद्धालु नाचते गाते थिरकते हुए बारत में चारभुजा नाथ का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। स्वर्णकार परिवार द्वारा पुष्प वर्षा पगबरना बिछाकर बारत का स्वागत किया। तोरण की रश्म के बाद स्वर्णकार परिवार द्वारा जोड़े बैठकर कुमारओड़ा, शालिलाल पाराशर, शंभू सिंह गहलोत, दिनेश कुमार सोनी, लोकेश कुमार सोनी , हरिशंकर पाराशर, प्रह्लाद राय पाराशर, सहित सिंगोली श्याम मित्र मंडल के सदस्य उपस्थित थे।

मेड़ता रोड में रेलवे फाटक सी-99 ए एक घंटे बंद रहने से वाहन चालक परेशान

वाहनों की लगी लंबी कतारें, आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित

स्मार्ट हलचल



कच्चे मार्गों से निकलते दिखाई दिए, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रही।

स्कूल बसों और मरीज भी फंसे

फाटक बंद रहने से सबसे अधिक परेशानी स्कूल से आने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को हुई। कुछ स्कूल बसों भी जाम में फंस गईं, जिससे बच्चे समय पर घर नहीं पहुंच सके। वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि एक-दो निजी वाहन मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए भी जाम में फंसे रहे। हालांकि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनी रही।

पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार

स्मार्ट हलचल | बानसूर

हरसौरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी जनमेजय ने बताया कि पुलिस को देवसन स्टैंड पर कुछ संदिग्ध युवकों के हथियारों के साथ खड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़कर खेतों की ओर भाग निकले। पुलिस ने पीछा कर बाबरिया बांध के पास से दो आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी में एक देसी कट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित जाट उर्फ गोल्ड निवासी नांगल जमालपुर, जिला रेवाड़ी और विकास गुजर निवासी गुवाडा के रूप में हुई है। पुलिस



ने अवैध हथियार और वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली है। मामले में तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस हथियारों की स्पलाई और आपराधिक गतिविधियों को लेकर गहन जांच कर रही है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान, 3 किलो प्लास्टिक जब्त



स्मार्ट हलचल | हरसौरा

जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मोड़ीकलां द्वारा सिंगल प्लास्टिक एवं प्लास्टिक कैरी बैग की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।

वीडीओ स्नेह कंवर शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान 9 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत ग्राम पंचायत की टीम द्वारा गांव के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 3 किलोग्राम

सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी हिदायत दी गई।

वीडीओ शेखावत ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल सीमित अवधि तक नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में भी नियमित रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें और गांव को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।

कार्रवाई के दौरान सरपंच पार्वती मातवा, कनिष्ठ लिपिक पुनाराम, सुनीता चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा: इबादत, अमन और रहमत की दुआओं से गूंज उठी मस्जिदें

शहर भर की मस्जिदों में अकीदतमदों की उमड़ी भीड़, रोजे के मसाइल पर इमामों ने डाली रोशनी

स्मार्ट हलचल

मेड़ता रोड। रमजानुल मुबारक के पहले जुम्मा के मौके पर मेड़ता रोड शहर की तमाम मस्जिदों में अकीदतमदों का सैलाब उमड़ पड़ा। सजदे में झुके हजारों सरों ने अल्लाह तआला से अमन, चैन, तरकी और ईमानियत की भलाई के लिए दुआएं मांगीं। मस्जिदों का माहौल पूरी तरह रूहानी रंग में रंगा नजर आया, जहां नमाजियों ने पूरे एहताराम और खशुअ-खुजू के साथ जुम्मे की नमाज अदा की।

जुम्मे के खूबे में इमामों ने रमजान की फजीलत बयान करते हुए रोजे के मसाइल, उसकी शर्तों और एहतियातों पर तफसील से रोशनी



डाली। उन्होंने कहा कि रोजा सिर्फ भूखे-प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि आंख, कान और जवान की हिफाजत का भी नाम है। रोजा इंसान को सब्र, तक्रवा और हमददी का सबक देता

है। इमामों ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि रमजान का महीना रहमत, माफिफत और जहनमा से निजात का महीना है। इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत,

तिलावात-ए-कुरआन, सदका व खैरात और जरूरतमदों की मदद करने की ताकदी की गई। उन्होंने रोजेदारों को झुट, गीबत और फिजूल बातों से बचने की नसीहत भी दी।

नमाज के बाद ख़ास दुआ का एहतामत किया गया, जिसमें मुल्क में अमन-ओ-अमान, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। मस्जिदों के बाहर भी रौनक का आलम रहा, जहां लोग एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद देते नजर आए। रमजानुल मुबारक के पहले जुम्मा ने एक बार फिर यह पैगाम दिया कि यह महीना सिर्फ इबादत का ही नहीं, बल्कि ईमानियत, मोहब्बत और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का भी है।

घंटे तक बंद रहता है, तो दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा बनी तो वे रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

आपातकालीन स्थिति में बंद सकता है खतरा

स्थानीय नागरिकों ने यह भी चिंता जताई कि यदि इस दौरान कोई गंभीर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती, जैसे एंबुलेंस को अस्पताल पहुंचना हो या किसी गर्भवती महिला को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो, तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लंबे समय तक फाटक बंद रहने से जान-माल का जोखिम भी बढ़ जाता है। रेलवे प्रशासन से समाधान की अपेक्षा घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी तकनीकी प्रक्रियाओं के दौरान फाटक को अधिक समय तक बंद न रखा जाए। यदि आवश्यक हो तो ट्रैफिक प्रबंधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए या पहले से सूचना जारी की जाए, ताकि आमजन को अस्वविधा न हो। फिलहाल इस मामले में रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान करेगा।

विभागों की खींचतान में उजड़ी 3.17 करोड़ की सड़क, बाजार में धूल और अव्यवस्था से जनता परेशान

स्मार्ट हलचल

नारायणपुर। सरकारी विभागों के बीच तालमेल के अभाव का एक बड़ा उदाहरण कस्बे के मुख्य बाजार में सामने आया है, जहाँ जलदाय विभाग की ओर से पाइप लाइन बिछाने के नाम पर स्टेट हाईवे-52 की हाल ही में बनी सड़क को जगह-जगह से उखाड़ दिया गया है। यह सड़क वर्ष 2020-21 में एनसीआर पीबी खंड द्वारा करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपये की लागत से तैयार की गई थी। निर्माण के दौरान 7 मीटर चौड़ी सीसी रोड बनाई गई थी तथा शोप हिस्से में टाइल वर्क कराया गया था, लेकिन अब करीब एक किलोमीटर तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और मलबे में तब्दील नजर आ रही है। सड़क की दुर्दशा से स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा



है। बाजार क्षेत्र में जेसीबी से की गई खुदाई के बाद गड्डे खुले छोड़ दिए गए हैं, जिससे धूल का गुबार दिन-रुन उड़ता रहता है। हालात यह हैं कि वाहन चालकों को फिसलन और दुर्घटना का डर बना रहता है, वहीं दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।

स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर विशेष आक्रोश है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 40-40

फीट अतिक्रमण हटाकर लंबे संघर्ष के पश्चात इस सड़क का निर्माण संभव हो पाया था, लेकिन अब उसी सड़क को बिना ठोस योजना के दोबारा तोड़ दिया गया। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब दो सरकारी विभाग आमने-सामने आ गए। जलदाय विभाग की जेडएन सुरीला सैनी का कहना है कि सड़क तोड़ने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से विधिवत अनुमति ली

भारत के सहयोग से म्यांमार के नाविकों को मिलेगी सिम्युलेटर बेसड ट्रेनिंग

स्मार्ट हलचल

नेपीडॉ। भारत के वित्तीय सहयोग से म्यांमार में एक दो मॉडल ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास हुआ है, जिसमें देश के नाविकों (सीफेयरर्स) के लिए सिम्युलेटर बेसड ट्रेनिंग, असेसमेंट और एजाम से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं आसानी से हो सकेंगी।

म्यांमार में भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित भूमि पूजन समारोह (ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी) में हिस्सा लिया। भारतीय दूतावास की ओर से कहा गया है, दो मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, जो 'सीफेयरर्स के लिए सिम्युलेटर बेसड ट्रेनिंग, असेसमेंट और एजाम सिस्टम' के लिए एक छोटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एसडीपी) है, के कंसट्रक्शन के लिए ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी आज यंगून में प्रोजेक्ट साइट पर हुई। दूतावास ने बताया कि कार्यक्रम में भारतीय राजदूत के अलावा यंगून रीजन गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर यू सोए थिन; ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन्स के



डिप्टी मिनिस्टर यू आंग क्याव तुन भी मौजूद रहे।

इस प्रोजेक्ट में सिम्युलेटर-बेसड ट्रेनिंग सेंटर के कंसट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ-साथ यंगून में सीफेयरर्स की ट्रेनिंग के लिए मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल सिम्युलेटर लगाने का प्लान है।

बयान में कहा गया है एसडीपी को लागू करने के लिए इंडियन ग्रांट असिस्टेंस के लिए फ्रैमवर्क एमओयू

पर असल में जुलाई 2010 में साइन किया गया था और यह जुलाई 2030 तक वैध है। इस सहयोग के तहत, भारत सरकार ने अलग-अलग एसडीपी प्रोजेक्ट्स को मदद दी है, जैसे कि सागाइंग इलाके के मोन्गवा में 500 बेड वाला हॉस्पिटल, रखाइन स्टेट में कंप्यूटर और एग्री-मशीनरी की स्पलाई और म्यांमार के कई राज्यों और इलाकों में होम साईंस स्कूलों को मदद। बता दें कि भारत अपनी 'पड़ोसी

डेयरी पर फायरिंग के 25000 रुपये के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार

स्मार्ट हलचल | बानसूर

सर्किल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की घटना में चार माह से फरार चल रहे 25000 रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि आरोपी ने 17 अक्टूबर को अपने साथियों के साथ मिलकर घासीनगर में एक दूध डेयरी पर फायरिंग की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था, मामले में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी भूपेंद्र सिंह निवासी इंदराड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल गोपेश कुमार की विशेष भूमिका रही।

लंबे जाम का पर्याय बना कानपुर, सागर हाईवे पर 30 किलोमीटर तक 12 घंटे जाम

स्मार्ट हलचल



कानपुर। पुलिस प्रशासन के लाभ प्रयासों के बावजूद भीयवंत जाम की समस्याहाल होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी मार्ग पर घंटों जाम ना लगता हो। इसी जाम की वजह से पूर्व में अस्पताल पहुंचने के पहले ही मरीजों की मौत भी हो चुकी है।

घंटों जाम की इस समस्या से कानपुर सागर हाईवे से गुजरने वाले लोगों को भी जूझना पड़ा। यहां पर 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इस भीषण जाम में एंबुलेंस और स्कूली वाहन भी घंटों फंसे रहे।

घंटों जाम लगने की यह नौबत तब आई जब बिधुनू थाना क्षेत्र के रमईपुर चौराहे के पास देर रात दो ट्रक खराब हो गए। जिसके बाद से जाम लग गया। पुलिस के मुताबिक रात होने के कारण कुछ वाहन चालक सो गए। जिसके कारण हाईवे पर वाहनों की कतारें लगातार बढ़ती चली गईं। सुबह होते-होते यह जाम करीब 30

किलोमीटर लंबा हो गया। जिससे हजारों वाहन चालक और यात्री घंटों टफ फंसे रहे। इनमें से कई मरीज भी फंसे हुए बताए गए। पुलिस के मुताबिक समाचार लिखे जाने तक खुलवाने में काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। अगर उन क्षेत्रों में जाम की समस्या की बात करें टाट मिल ,रामादेवी चौराहा रावतपुर ,विजयनगर ,फजलगंज नौबस्ता यशोदा नगर में भी लोग जाम की समस्या से जूझते रहते हैं। कई जगह बनाए गये ट्रैफिक के कट भी जाम का कारण बनने से नहीं चुकते। कुल मिलाकर महानगर को लाख प्रयासों के बाद भी जाम की समस्या से पूर्ण रूप से निजात अभी तक नहीं मिल पाई है।

बानसूर में 22 फरवरी को होगी अहीर महापंचायत



स्मार्ट हलचल | बानसूर

यादव समाज द्वारा सामाजिक कृूरितियों को दूर करने के लिए रविवार को अहीर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर यादव छात्रवास में समाज सुधार कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। समाज के पूर्व अध्यक्ष किशन लाल यादव ने बताया कि इस महापंचायत में समाज के सभी वर्तमान एवं पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, चैयर्सन, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य, सरपंच और समाज के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय सभी पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। यादव ने यह भी बताया

कि 100 दिन की कार्य योजना में लिए गए निर्णयों को 22 फरवरी को साधु-संतों की उपस्थिति में लागू किया जाएगा इस महापंचायत में बानसूर, नारायणपुर, विराट नगर, पावटा, कोटपुतली, बहरोड़, नीमराना, मुंडावर, कोटकासिम, तिजारा, किशानगढ़, खैरथल, अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों से यादव समाज के लोग भाग लेंगे। बैठक में कांग्रेस के पूर्व ब्लाक अध्यक्ष अजय यादव, पूर्व सरपंच रामसिंह, उद्योगपति रमेश यादव, मास्टर मातादीन यादव, रोहिताश्व, देवराज, प्रकाश यादव, अजय गुरुजी, प्रमोद यादव, कैप्टन हरीराम, जयमल नेता, देवीदयाल, सुरेंद्र कवि और कैलाश यादव सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

बिजली विभाग ने कई गांवों में चलाया राजस्व वसूली अभियान

लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया चलते हुई कार्यवाही

स्मार्ट हलचल | बानसूर

क्षेत्र में बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने बबेड़ी, मांवी, रामनगर और बकाया अहियान चलाया। इस दौरान बकाया राशि का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के कुल 8 ट्रांसफार्मर हटा दिए गए। रामनगर के सहायक अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि ये अभियान बहरोड़ की टीम के साथ मिलकर चलाया गया। संबंधित उपभोक्ताओं पर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया था। विभाग ने पहले भी नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने के निर्देश



दिए थे। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान न होने पर ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें समय रहते भुगतान करने की सलाह दी गई है, अन्यथा उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

टीकाकरण अभियान को मिली नई गति डब्ल्यूएचओ ने ब्लॉक शिव में कार्ययोजना का गहन किया विश्लेषण

स्मार्ट हलचल | शिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खण्ड शिव में संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विष्णुगाम विश्वांस के निर्देशन में आयोजित की गई। ब्लॉक शिव में नियमित टीकाकरण कार्ययोजना को नई दिशा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की प्रतिनिधि डॉ पल्लवी राव ने आज गहन विश्लेषण किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला स्तर से अशोक गोड ने प्रभावशाली प्रेजेंटेशन देकर अभियान की चुनौतियों व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बैठक में उपस्थित सभी सीएचओ, एएनएम एवं ओपरेटर को निर्देशित किया की गर्भवती महिला का पंजीयन, एनसीडी कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड



तथा 70ई केवाईसी, संस्थागत प्रसव, सभी बच्चों का समय पर टीकाकरण एवं परिवार कल्याण की उपलब्धि शत प्रतिशत पूर्ण की जाये, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना महत्वपूर्ण योजना है इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ माधुराम कुमावत ने चिकित्सा संस्थानवार पीपीटी के माध्यम से समस्त गतिविधियों पर समीक्षा की

संचालित योजनाओं की प्रगति से सभी को अवगत करवाया, टीबी मुक्त भारत, परिवार कल्याण, आईएचआईपी पोर्टल, एचएमआई पोर्टल, मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु सामाजिक समीक्षा आदि कार्यक्रमों की समीक्षा कर कार्य में उपलब्धि अर्जित करने हेतु अवगत करवाया गया। राजेश जनालग बीएचएस द्वारा एनसीडी पोर्टल, आशा सांफ्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री अरविंद कुमार कॉडीनेटर ने एनीमिया मुक्त राजस्थान प्रोग्राम आईएफएफ सिस्फ, आईएफए टैबलेट के समय पर डिमाण्ड एवं स्कूल, आगनवाड़ी केन्द्र, चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्धता पर चर्चा की। बैठक में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, एलएचवी, एमपीडब्ल्यू, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सीएचओ एवं एएनएम आदि उच्चस्थरों से जुड़े विभाग द्वारा

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तार: एक सार्थक पुकार



ललित गर्ग

सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-समी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम 'समावेश को सशक्त बनाना: सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना' हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं—चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है। आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार अत्यधिक हो जा रहा है। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक ताने को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है।



मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है। समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। 'संतुष्टिकरण'

बनाना 'संतुष्टिकरण' की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियाँ शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है। आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धर्मतंत्र एवं सत्तारंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, प्रॉक्सि बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।' रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि 'मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।' लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त

न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियाँ पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है। सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी जेबों को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों को सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कण्टक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके। 2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यदि हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संरक्षितता का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।

संपादकीय

अपराध की मंशा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करना, जिसमें हवलालाकर के प्रयास की परिभाषा बदल दी गई थी, केवल एक कानूनी सुधार मात्र नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह न्यायिक संवेदनशीलता और गंभीर मामलों में न्यायिक दृष्टि की स्पष्टता की पुनः पुष्टि भी है। सर्वोच्च अदालत ने पाँवसे एकट के साथ ही धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप बहाल करके, इस बात पर भी बल दिया कि अपराध के इरादे को, प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कमतर नहीं माना जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस बाबत जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर तल्लक प्रतिक्रियाएँ सामने आई थीं, जिसे किसी सभ्य समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल माना गया था। दरअसल, हाई कोर्ट ने माना था कि एक नाबालिग के उरोज पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी ढीली करना और उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास दुर्गन्ध का तैयारी थी, न कि बलात्कार का प्रयास, क्योंकि इसमें अपराध की दिशा में कोई सीधा कदम नहीं उठाया गया था। स्वाभाविक रूप से इस तरह की संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ समाज में प्रतिक्रिया होनी ही थी। कहीं न कहीं इस तंत्र व्याख्या से अपराधी के जन्म इरादे और प्रयास की अवधारणा को कमजोर करने का जोखिम भी था। निस्संदेह, इस तरह की व्याख्या से महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद ही होते। जाहिर है इस तरह की सोच कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह सुखद ही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संकीर्ण व्याख्या वाले मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्थक हस्तक्षेप किया है। दरअसल, आपराधिक कानून में, प्रयास तब माना जाता है, जब किसी अपराध की तैयारी उस कृत्य को अंजाम देने में बदल जाती है। जो कि इच्छित अपराध के निकट होती है। इस मामले में आरोप- शारीरिक छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने और जबन घसीटना, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न की ओर एक सुनिश्चित कदम की पुष्टि कर देते हैं। जिसे केवल पीड़िता के कष्टपूर्ण अनुभव से ही प्रत्यक्षदर्शियों के हस्तक्षेप से ही रोका गया। निस्संदेह, इसके विपरीत मानना यौन हिंसा की वास्तविकताओं और नाबालिगों की असुरक्षा को अनदेखा करना ही होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह फैसला आरोपों की गंभीरता को पुष्टि करता है। ताकि पूर्व सुनवाई में साक्ष्यों की उचित संदर्भ में जांच की जा सके। ऐसे वक्त में जब देश की कई अदालतों के लैंगिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण को कड़ी आलोचना हो रही थी, यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि कानूनी तर्कों को संवैधानिक मूल्यों को बनाये भी रखना चाहिए। निर्विवाद रूप से, जिनका उद्देश्य किसी सभ्य समाज में नागरिकों को आसन खतरे से भी बचाना ही होता है। बहरहाल, इस प्रकरण में यह सार्थक हस्तक्षेप इस बात की पुष्टि भी करता है कि कानून बच्चों को न केवल अपराधियों द्वारा अंजाम दिए जा चुके अपराधों से बल्कि भविष्य में आसन अपराधों से भी बचाता है। इस प्रकरण के बाद कहा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल न्यायिक जवाबदेही में संतुलन स्थापित किया, बल्कि आखिरकार आम लोगों के विश्वास को भी बहाल किया है।

चितन-मनन

सच को छुपाने का परिणाम

एक बार की बात है। एक व्यक्ति का पुत्र कमाने की लूट विदेश गया। विदेश कमाने गए पुत्र ने अपने पिता को एक बहुत ही सुंदर अंगूठी भेजी। पत्र में उसने लिखा, 'पिताजी! आपको मैं एक अंगूठी भेज रहा हूँ। उसका मूल्य है पाँच हजार रूपए। मुझे सस्ते में मिल गई थी, इसलिए मैंने आपके लिए खरीद ली।' बेटे द्वारा भेजी गई अत्यंत सुंदर अंगूठी पाकर पिता प्रसन्न हो गया। पिता ने बड़े शोक से वह अंगूठी पहन ली। अंगूठी बहुत ही चमकदार और सुन्दर थी। बाजार में पिता को कई मित्र मिले। नई अंगूठी को देख कर सबने पूछा, 'यह कहाँ से आई?' पिता ने कहा, 'मेरे लड़के ने विदेश से भेजी है। इसे खरीदने में उसने पाँच हजार रूपए खर्च किए।' पिता का एक मित्र बोला, 'क्या इसे बेचोगे?' में इस अंगूठी के पचास हजार रुपये दूंगा।' पिता ने सोचा, पाँच हजार की अंगूठी के पचास हजार रुपये मिल रहे हैं। इसने रूपयों में ऐसी दस अंगूठियाँ आ जाएगी। उसने अंगूठी निकाल कर दे दी और अपने मित्र से पचास हजार रूपए ले लिए। फिर उसने पुत्र को पत्र लिखा, 'तुमने शुभ मुहूर्त में अंगूठी भेजी। उसमें मैंने पचास हजार रूपए में बेच कर पैतलीस हजार रूपए का लाभ अर्जित कर लिया।' लौटती डाक से पुत्र का पत्र आया, 'पिताजी! संकोच और भयवश मैंने आपको पिछले पत्र में सच्चाई नहीं लिखी थी। वह अंगूठी एक लाख की थी।' यह सत्य को झुठलाने का परिणाम था।



कालिला मांडोट

हाल के वर्षों में उपग्रह तस्वीरों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह संकेत मिले हैं कि चीन अपने सामरिक दांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है। दक्षिण-पश्चिमी प्रांतों में पहाड़ों के भीतर बने बड़े-बड़े बंकर, भूमिगत सुरंगें और अत्याधुनिक सुविधाएँ इस ओर इशारा करती हैं कि बीजिंग अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर चुपचाप काम कर रहा है। ऐसे समय में जब वह भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने और सहयोग बढ़ाने की बात करता है, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या चीन वास्तव में भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है या यह उसकी रणनीतिक नीति का हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के संबंधों में विश्वास की कमी की जड़ें गहरी हैं। वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर किया गया हमला दोनों देशों के रिश्तों में एक स्थायी अविश्वास की दीवार खड़ी कर गया। उसके बाद से सीमा विवाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और समय-समय पर होने वाली झड़पों ने यह स्पष्ट किया कि संबंधों में गर्मजोशी और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर है। चीन ने कई बार शांति और सहयोग की बात की, लेकिन समानांतर रूप से अपनी सैन्य और



निर्मल रानी

इ नदियों एस्पटीन फाइल्स का भूत अमेरिका से लेकर भारत तक सड़कों पर नाच रहा है। अमेरिकी कग्रेस के कानून के अन्तर्गत और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हस्ताक्षर के बाद ही अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा यह फाइल्स जारी की गई हैं। इस आदेश के तहत अमेरिकी न्याय विभाग को एस्पटीन से जुड़े सभी अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, कानूनीकृत निर्देशन रेखा पर तनाव करने का निर्देश प्राप्त है। हालाँकि यह कानून 2025 में कांग्रेस के दोनों सदनों (हाउस और सेंनेट) से लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ था, और राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 नवंबर 2025 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसी कानून के तहत अमेरिकी न्याय विभाग ने समय-समय पर फाइल्स जारी की। परन्तु इन फाइल्स का बड़ा हिस्सा गत 30 जनवरी 2026 को जारी किया गया, जिसमें 3.5 मिलियन से ज्यादा पृष्ठ, 2,000 से अधिक वीडियो और लगभग 1,80,000 फोटो शामिल थे। एस्पटीन फाइल्स के इसी खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया के जाने माने लोगों के चेहरे से नकाब हटने लगी। इन फाइल्स के संवैधानिक

चीन की नई कूटनीति या पुरानी चाल? भारत के लिए भरोसा या भविष्य का धोखा

सामरिक ताकत को भी बढ़ाया। चीन की विदेश नीति को समझने के लिए उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को देखना जरूरी है। वह ताकालिक भावनाओं के बजाय दशकों आगे की योजना बनाकर चलता है। उसकी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विस्तार है। चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो, ताइवान का मुद्दा हो या हिमालयी सीमा हर जगह उसकी नीति शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने की रही है। ऐसे में यदि वह भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल करता है, तो यह केवल सद्भावना का परिणाम नहीं बल्कि एक सुविचारित रणनीति भी हो सकती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में चीन कई मोर्चों पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक तनाव, तकनीकी प्रतिबंध और सामरिक प्रतिस्पर्धा ने उसे नए संतुलन की तलाश में डाल दिया है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है। एशिया में स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भारत के साथ टकराव चीन के हित में नहीं है। इसलिए संभव है कि वह सीमित सहयोग और नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाए, ताकि वह एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष से बच सके। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि चीन की नीतियों में पारदर्शिता का अभाव रहा है। उसकी सैन्य तैयारियों और परमाणु दांचे के विस्तार को लेकर अक्सर बाहरी दुनिया को सीमित जानकारी ही मिलती है। यदि उपग्रह तस्वीरों में दिखाई देने वाले निर्माण सचमुच सामरिक क्षमताओं के विस्तार का संकेत हैं, तो यह भारत सहित पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। एक ओर संवाद और व्यापार की बातें, दूसरी ओर पहाड़ों के भीतर बनते ठिकाने यह दोहरी तस्वीर सहज भरोसा पैदा नहीं करती।

भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह चीन के इरादों को कैसे परखे। केवल बयानों के आधार पर विश्वास करना रणनीतिक भूल हो सकती है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संवाद के द्वार खुले रखने होंगे। कूटनीति में संतुलन और सैन्य तैयारी में सतर्कता दोनों समान रूप से जरूरी हैं। चीन के साथ संबंधों को पूरी तरह टकराव की दिशा में ले जाना भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं और परस्पर निर्भरता भी बढ़ी है। चीन की निर्यात को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि वह वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। उसकी बेल्ट एंड रोड पहल, तकनीकी निवेश और वैश्विक संस्थाओं में बढ़ती भूमिका इस दिशा का संकेत देती है। ऐसे में वह भारत को प्रतिस्पर्धी भी मानता है और संभावित साझेदार भी। यदि भारत उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती बनता है, तो प्रतिस्पर्धा तीखी हो सकती है। लेकिन यदि भारत संतुलित और आत्मविश्वासी नीति अपनाता है, तो सहयोग के अवसर भी बन सकते हैं। भरोसा का निर्माण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से होता है। सीमा पर शांति, समझौतों का पालन और पारदर्शिता ये वे कसौटियाँ हैं जिन पर चीन को परखा जाएगा। यदि वह सचमुच स्थिर और सकारात्मक संबंध चाहता है, तो उसे ठोस कदम उठाने होंगे। अन्यथा, इतिहास का अनुभव यही बताता है कि रणनीतिक मित्रता के पीछे छिपी चालों को समझने में देर नहीं लगती। भारत को भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। चीन न तो पूरी तरह भरोसेमंद मित्र है और न ही अनिर्वाय शत्रु। वह एक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर राष्ट्र है, जिसकी प्राथमिकता उसके अपने हित हैं। भारत के साथ उसके संबंध भी



इन्होंने हितों की कसौटी पर तय होंगे। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि चीन सहयोग की राह चुनता है या प्रतिस्पर्धा और दबाव की नीति पर कायम रहता है। भारत के लिए जरूरी है कि वह सतर्कता, आत्मनिर्भरता और संतुलित कूटनीति के सहारे हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार रहे।

एस्पटीन फाइल्स : यही है शक्तिशाली पुरुष भेड़ियों की हकीकत

के बाद एस्पटीन के यौन अपराधों, ट्रैफिकिंग नेटवर्क और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों की गहराई उजागर हुई। गौरतलब है कि जेफरी एस्पटीन, एक अमीर फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी है। इसने अनेक नाबालिग लड़कियों और युवा महिलाओं का शोषण किया, और इन फाइल्स में राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक हस्तियों के कई नाम सामने आए। इन खुलासों के बाद कई प्रमुख व्यक्तियों का भविष्य व जीवन प्रभावित हुआ। कई लोगों को इस्तीफे देने पड़े तो कई के विरुद्ध जांच बिठाई गयी। आपना नाम आने पर कई लोग शर्मिंदगी से जहाँ मुंह छुपाते घूम रहे हैं वहीं तक कि इस नेटवर्क में नाम आने के बाद कई लोग भूमिगत हो चुके हैं और मीडिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वहीं भारत में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जैसे विशिष्ट भी हैं जो एस्पटीन फाइल्स के खुलासे के अनुसार तो जेफरी एस्पटीन से 14 बार मिले परन्तु वे स्वयं एस्पटीन से 8 सालों में केवल 3-4 बार की मुलाकात को ही स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद वह इस सवाल से बच नहीं पा रहे कि 13-14 बार या 3-4 बार नहीं बल्कि यदि एक सजायाप्राप्त बदनमान यौन अपराधी से हरदीप पुरी एक बार भी मिले तो उस मुलाकात की वजह क्या थी? जो व्यक्ति खुद स्वीकार कर चुका है कि वह कम उम्र की बच्चियों से सैक्स करने का आदी था ऐसे भेड़िया मानसिकता वाले व्यक्ति से मुलाकात क्यों की गयी? किसके कहने पर या किसके लिये की गयी? बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि अभी दुनिया के और भी अनेकानेक सफेदपोश भेड़ियों के नाम सामने आएंगे और इस्तीफों की भी झड़ी लग सकती है।

ऐसी हैं जो पितृ सत्ता या पुरुष प्रधान समाज का बार बार एहसास करती हैं। परन्तु इस घटना में तो जेफरी एस्पटीन पर 2019 में न्यूयॉर्क में संघीय अदालत ने उसपर सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइंस के आरोप लगाए, जिसमें दर्जनों नाबालिग लड़कियाँ यहाँ तक कि 14 साल से भी कम उम्र की कुछ बच्चियों का यौन शोषण शामिल था। यह उसकी स्वीकारोक्ति थी कि उसने नाबालिग लड़कियों से यौन संबंध बनाये व अवैध काम किए। इसलिये इस विश्वव्यापी नेटवर्क से पर्दा उठने के बाद अब यह सवाल भी उठने लगा है कि दुनिया के धनाढ्य और शक्तिशाली लोगों की नजर में महिलाओं, खासकर छोटी बच्चियों का क्या स्थान है? महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का ढोंग रचने वाला सफेद पोश पुरुष प्रधान समाज जो कभी महिलाओं को आधी आवादी कहकर खुश करता है तो कभी बच्चियों को कंकज व देवी के रूप में पूजा भी है उन्हीं बच्चियों को अपने पैसे व सत्ता के बल पर अपनी हवस का निशाना बनाने वाले लोग नाबालिग लड़कियों और युवा महिलाओं का शारीरिक शोषण भी करते हैं? निश्चित रूप से एस्पटीन फाइल्स पितृसत्ता की एक गहरी तस्वीर पेश करती हैं, जहाँ धनाढ्य पुरुष विश्वव्यापी नेटवर्क बनाते हैं और एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं और महिलाओं को परिधि पर रखते हैं। वास्तव में आधी आवादी को प्रायः सहयोगी, या यौन सुख प्रदान करने वाली के रूप में ही देखा जाता है न कि समान भागीदार के रूप में। खासकर गरीब परिवारों की छोटी बच्चियों को तो कमजोर और आसानी से नियंत्रित करने योग्य माना जाता था। एस्पटीन के नेटवर्क में शामिल कुछ पुरुषों ने कथित तौर पर इन लड़कियों को उपहार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे व्यापारिक या

राजनीतिक लाभ मिलते थे। यह दशाती है कि शक्तिशाली लोगों की नजर में, महिलाएँ और लड़कियाँ अक्सर सत्ता और प्रभाव बनाए रखने का साधन बन जाती हैं न कि कोई सम्मानजनक मानव। महिलाओं को केवल प्रजनन उपकरण के रूप में देखा भी पितृसत्ता की ही एक गहरी साजिश है। इसलिये एस्पटीन फाइल्स से प्राप्त हो रहे व्यौरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एस्पटीन जैसे मामलों में जहाँ कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा छोटी बच्चियों को मात्र अपनी यौन संतुष्टि के लिये या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौदेबाजी के साधन के रूप में अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को ब्लैकमेल करने की गरज से इस्तेमाल किया गया यह एक ऐसी व्यवस्थित समस्या है जहाँ धन, सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण नस्लवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालाँकि, FBI की जांच में ट्रैफिकिंग रिंग के लिए पर्याप्त सबूत भले ही नहीं मिले परन्तु पीड़ितों की गवाहियाँ बताती हैं कि यह शोषण अत्यंत व्यापक था। ये फाइल्स यह भी दिखाती हैं कि सत्ता के बल पर और जवाबदेही की कमी से ऐसी संस्कृति पनपती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैश्विक अपरा

काले चने गुड़ के साथ खाने से एनीमिया जल्द खत्म हो जाता है



खून में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी को एनीमिया कहते हैं। कई बार शरीर रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन बना नहीं पाता और कई बार ज्यादा खून बह जाने से शरीर में इनकी कमी हो जाती है। एनीमिया

को एक तरह की बीमारी माना जाता है। ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं को होती है और उनमें इसकी एक मुख्य वजह मासिक धर्म होता है। आमतौर पर पुरुषों में 100 मिली ग्राम खून में 13.5 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन

और महिलाओं में 100 मिली ग्राम खून में 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो तो इसे एनीमिया की स्थिति कहते हैं। कई बार एनीमिया के मरीजों में बाहर से कोई लक्षण नहीं नजर आते या हल्के-फुल्के लक्षण नजर आते हैं

जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। खून की सीबीसी जांच द्वारा इस बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

एनीमिया का कारण

एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 3-5 ग्राम आयरन होता है। शरीर में इसकी मात्रा कम होने पर खून कम बन पाता है और एनीमिया हो जाता है। कई बार ज्यादा मात्रा में खून बह जाना भी एनीमिया का कारण बनता है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की अधिकता से भी एनीमिया हो सकता है इसलिए कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थों का बहुत अधिक सेवन भी शरीर के लिए

खतरनाक है।

एनीमिया से बचाव

एनीमिया से बचाव के लिए आपको अपनी जीवनशैली में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। एनीमिया मुख्यतः शरीर में खून की कमी ही है इसलिए इससे बचाव के लिए ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिससे शरीर में खून की मात्रा बढ़े जैसे- चुकंदर, गाजर, पालक, टमाटर, बथुआ और अन्य हरी सब्जियां। के साथ-साथ काले चने और गुड़ में भी आयरन भरपूर होता है। रोजाना सुबह भोगे हुए काले चने गुड़ के साथ खाने से एनीमिया जल्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सब्जी बनाने के लिए लोहे की कड़ाही का इस्तेमाल

एनीमिया के लक्षण

काम के दौरान जल्दी थक जाना दिनभर कमजोरी महसूस होना त्वचा पीली पड़ना सीढ़ी चढ़ते हुए चक्कर आ जाना सीने और सिर में दर्द होना तलवों और हथेलियों का ठंडा हो जाना

करते हैं तो इससे भी शरीर में आयरन की कमी दूर होती है। शरीर में आयरन की ज्यादा कमी होने पर आप चिकित्सक की सलाह से आयरन की गोतियां भी ले सकते हैं।

सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है किशमिश के पानी

किशमिश के पानी सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। इससे पेट की एक-दो नहीं बल्कि कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। किशमिश में मौजूद तत्व शरीर की पूरी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और इससे आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है और कब्ज, गैस आदि की दिक्कत नहीं होती है। सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं, लेकिन किशमिश का पानी सेहत के लिए और भी फायदेमंद होता है। किशमिश में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि पानी के साथ मिलकर ज्यादा असरदार हो जाते हैं। इसके लिए रात के समय एक गिलास पानी में 8 से 10 किशमिश भिगोकर रख दें और सुबह इसे अच्छी तरह पीस लें। अगली सुबह किशमिश छान कर पानी को पीने लायक गरम करें और इसे खाली पेट पिएं। किशमिश का पानी पीने के बाद 30 से 35 मिनट तक इंतजार करें और फिर नाश्ता करें। किशमिश का पानी लीवर में बायोकेमिकल प्रोसेस शुरू करता है, जिससे खून तेजी साफ से होने लगता है। इसके अलावा किशमिश में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किशमिश का पानी पीने के ओर भी फायदे।



दांतों के लिए : किशमिश में ऑलिलानॉलिक एसिड होता है जो कि फाइटोकेमिकल्स में से एक है और यह दांतों को केविटी और कई दिक्कतों से बचाता है। साथ ही किशमिश दांतों में बैक्टीरिया फैलने से रोकता है और दांतों को सुरक्षित रखता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह आपके दांतों को टूटने से बचाता है।

स्किन के लिए : किशमिश के पानी में फ्लेवोनॉइड्स एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्किन पर होने वाली झुर्रियों को तेजी से कम करने में सहायक है। यह बढ़ती उम्र के निशान को कम कर आपको जवां दिखने में मदद करता है।

सांसों की बढ़बू के लिए : किशमिश में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इससे बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता मिलती है और मुंह से आने वाली बदबू दूर होती है। इसके अलावा इसका उपयोग कई हेल्थ टॉनिक में भी किया जाता है।

पेट संबंधी रोगों के लिए : किशमिश के पानी से पेट की एक-दो नहीं बल्कि कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। किशमिश में मौजूद तत्व शरीर की पूरी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और इससे आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है और कब्ज, गैस आदि की दिक्कत नहीं होती है। साथ ही इसके नियमित सेवन से थकान भी दूर रहती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है।

हार्ट प्रॉब्लम के लिए : हर रोज किशमिश का पानी उन लोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है जो अधिक कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से परेशान हैं और उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल किशमिश का पानी शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मददगार है। इससे आपके शरीर में हर्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है।

आंखों के लिए : किशमिश में पॉलीफेनॉलिक फायटोकेमिकल्स होते हैं जो कि एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं और यह आंखों की आई साइड को ठीक रखने में मदद करती है। इसमें कई तरह के एंटी बॉयटिक और एंटी ऑक्सीडेंट फिनॉलिक पायथोकेमिकल्स तत्व होते हैं जो कि बुखार को भी ठीक कर देते हैं।

युवाओं में तनाव से बढ़ रहे हृदयाघात के मामले



भारतीय युवाओं में हृदयाघात की समस्या बढ़ती जा रही है और यदि इस समस्या पर रोक के उपाय नहीं किए गए तो यह महामारी का रूप ले कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार हृदय रोग की

महामारी को रोकने का एकमात्र तरीका लोगों को शिक्षित करना है।

आम तौर पर दिल के दौरों का संबंध पहले बुढ़ापे से माना जाता था लेकिन अब अधिकतर लोग उम्र के दूसरे, तीसरे और चौथे दशक के दौरान ही

दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। आधुनिक जीवन के बढ़ते तनाव ने युवाओं में दिल की बीमारियों के खतरे पैदा कर दिया है हालांकि अनुवांशिक और पारिवारिक इतिहास अब भी सबसे आम और अनियंत्रित जोखिम कारक बना हुआ है, लेकिन युवा पीढ़ी में अधिकतर हृदय रोग का कारण

समान लक्षण नहीं होते

सभी हृदय रोगियों में समान लक्षण नहीं होते हैं और एंजाइना छाती का दर्द इसका सबसे आम लक्षण नहीं है। कुछ लोगों को अपच की तरह असहज महसूस हो सकता है और कुछ मामलों में गंभीर दर्द, भारीपन या जकड़न हो सकता है। आमतौर पर दर्द छाती के बीच में महसूस होता है, जो बाहों, गर्दन, जबड़े और यहां तक कि पेट तक फैलता है, और साथ ही धड़कन का बढ़ना और सांस लेने में समस्या होती है।

अगर धमनियां पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती हैं, तो दिल का दौरा पड़ सकता है, जो हृदय की मांसपेशियों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। दिल के दौरे में होने वाले दर्द में पसीना आना, चक्कर आना, मतली और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

अत्यधिक तनाव और लगातार लंबे समय तक काम करने के साथ-साथ अनियमित नींद पैटर्न हैं। धूम्रपान और आराम तलब जीवनशैली भी 20 से 30 साल के आयु वर्ग के लोगों में इसके जोखिम को बढ़ा रही है।

ओपन हार्ट सर्जरी के मामले बढ़े

देश में हृदय अस्पतालों में दो लाख से अधिक ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है और इसमें सालाना 25 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यह सर्जरी केवल तात्कालिक लाभ के लिए होती है। हृदय रोग के कारण होने वाली मौतों को

रोकने के लिए लोगों को हृदय रोग और इसके जोखिम कारकों के बारे में अवगत कराना महत्वपूर्ण है।

कोरोनरी हृदय रोग ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन इसके इलाज से लक्षणों का प्रबंधन करने, दिल की कार्यप्रणाली में सुधार करने और दिल के दौरे जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए जीवनशैली में परिवर्तन, दवाएं और नॉन-इंवेसिव उपचार शामिल हैं। अधिक गंभीर मामलों में इंवेसिव और शल्य चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।



संक्रमण से होती है आंखें लाल

आंख लाल होने की समस्या तब होती है जब आंख की सतह पर मौजूद रक्त वाहिकाएं फैलती हैं या चोड़ी होती हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी आंख में कोई बाहरी चीज चली जाती है या कोई संक्रमण होता है। आंख आमतौर पर कुछ समय के लिए लाल हो जाती है। इसके साथ आंख में दर्द, आंखों में खुजली, रिसाव, आंखों की सूजन और धुंधला दिखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आंख लाल होने में या तो आंखों का पूरा सफेद हिस्सा लाल दिखने लगता है या कुछ रक्त वाहिकाएं सूज कर लाल हो जाती हैं। अगर आपकी आंख ठीक नहीं होती और लाली बढ़ती है, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं।

लक्षण

आंख में खुजली होना आंख से ज्यादा आंसू आना आंख से रिसाव होना प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता धुंधला दिखना नजर कमजोर होना एक या दोनों आंखों में किरकिराहट महसूस होना देखने या पढ़ने के बाद असहजता महसूस होना

कारण

इन कारणों से लाल होती हैं आंखें सूखे बाल मिट्टी ऐलर्जी ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखाएं आंख में हाल ही में चोट लगी है अगर आप नजर में बदलाव, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, तेज सिरदर्द जैसे लक्षण अनुभव कर रहे हैं। ज्यादा दर्द हो रहा हो। सिर पर चोट लगी हो। किसी रसायन से आंख में चोट पहुंची हो

बचाव

आंखों को न मलें। आंखें मलने से इन्फेक्शन व ऐलर्जी करने वाले बैक्टीरिया चले जाते हैं। जोर से आंख मलने से कॉर्निया में खरोंच और सबकन्जिक्टिवाइटल हेमरेज हो सकता है। धुएं, भाप, पराग, मिट्टी और क्लोरीन जैसे उत्तेजक पदार्थों से दूर रहें। अपने कॉन्टैक्ट लेंस की सही से देखभाल करें। कॉन्टैक्ट लेंस को ज्यादा समय तक न पहनें और इन्हें पहन कर न सोएं।

